https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'कांग्रेस का घोषणा-पत्र देश की सुरक्षा पर प्रहार'

वर्ष-14, अंक-08 16-30 अप्रैल, 2019 (पाक्षिक) ₹20

संकल्पित भारत सशक्त भारत

भारतीय जनता पार्टी

संकल्प पत्र

लोकसभा 2019

130 करोड़ सपनों का एक नया भारत

कासगंज (उत्तर प्रदेश) की एक रैली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का स्वागत करते उप्र भाजपा नेतागण

नागपुर (महाराष्ट्र) की एक विशाल रैली में जनाभिवादन स्वीकार करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी और भाजपा गठबंधन के नेतागण

अहमदाबाद (गुजरात) में जन संपर्क अभियान के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर पं. दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी को पुष्पांजलि अर्पित करते केंद्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल और अन्य

गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) में विजय संकल्प सभा के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह का स्वागत करते उप्र भाजपा नेतागण

रामटेक (महाराष्ट्र) में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

लोकसभा चुनाव हेतु भाजपा 'संकल्प पत्र' जारी

06

देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, भाजपा की संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष एवं देश के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज...

वैचारिकी

एकांगी नहीं, समाज का सर्वांगीण विचार आवश्यक 23

श्रद्धांजलि

महात्मा ज्योतिबा फुले / सुन्दर सिंह भण्डारी 25

लेख

संस्थानों को नष्ट करने और आतंकवादियों की मदद करने... 26

अन्य

130 करोड़ देशवासियों के सपनों का नया भारत 10

कांग्रेस का घोषणा-पत्र देश की सुरक्षा पर प्रहार : अमित शाह 11

संकल्प पत्र में हैं ये खास बातें 13

'चौकीदार' एक स्पिरिट है, एक भावना है : नरेन्द्र मोदी 18

भारत में डिजिटलीकरण के चलते धोखाधड़ी के मामलों में... 21

नवीन सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान 30

भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से लाइव सैटेलाइट को मार... 33

17 भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गांधीनगर सीट से किया नामांकन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 30 मार्च को गुजरात के गांधीनगर लोकसभा सीट से...

28 'पाकिस्तान को सीधा करने वाला एक ही नाम है नरेंद्र मोदी'

लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10 अप्रैल को गुजरात पहुंचे। जूनागढ़ में एक आम सभा को संबोधित करने के बाद...

20 भारत ने अंतरिक्ष में मार करने वाली मिसाइल का किया सफल परीक्षण

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 27 मार्च को ओडिशा स्थित डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप से...

22 एलसीयू एल-56 जहाज नौसेना में शामिल

यार्ड 2097 (एलएसयू एल-56), लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी (एलसीयू) एमके-IV छठी श्रेणी का...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

महामिलावट को हमसे डर लगता है क्योंकि:
भ्रष्टाचार की सारी दुकानें बंद हो जाती हैं।
रक्षा सौदों में मलाई नहीं मिलती।
गरीबों के नाम पर ठगी बंद रहती है।
जाति और धर्म पर आधारित इनकी राजनीति ठप रहती है।
टुकड़े-टुकड़े गैंग खुद टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर जाती है।

@AmitShah

पूरा देश अपने लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ चौकीदार बनकर खड़ा है। मोदी जी में जनता का यह अटूट विश्वास देखकर मैं दावे से कह सकता हूं कि प्रचंड बहुमत वाली 'फिर एक बार मोदी सरकार' बनना तय है।

@Ramlal

भ्रष्टाचार कांग्रेस का मूल स्वभाव है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में आये अभी चार महीने भी नहीं हुए और इतना बड़ा डाका जनता के टैक्स की कमाई पर.. स्पष्ट है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश सरकारों को अपने लिए ATM बना लिया है।

facebook

पिछले पांच वर्षों में मोदी सरकार ने खिलाड़ियों को विशेष प्रोत्साहन और सुविधाएं दी हैं, जिसके कारण अब अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रदर्शन अच्छा हुआ है। भारत के युवा भी 130 करोड़ हिन्दुस्तानियों के लोकप्रिय कप्तान नरेंद्र मोदी जी की अगली पारी में उनका सहयोग देने के लिये एक जुट हो चुके हैं। — **रविशंकर प्रसाद**

गरीबी के कारण दशकों से स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित जनता को आयुष्मान योजना के द्वारा 5 लाख तक निःशुल्क इलाज की सुविधा मिली। अब गरीब को इलाज के लिए न कर्ज लेना पड़ेगा, न घर बेचना पड़ेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और विकास से संभव हुआ। — **पीयूष गोयल**

कांग्रेस की सरकार में एक रुपया चलता था, तो जनता तक केवल 15 पैसे पहुंचता था। ज़मीन से लेकर आसमान तक कांग्रेस में घोटाला होता रहा है। मध्यप्रदेश में 100 दिन में ही 281 करोड़ निकले हैं। एक शक्तिशाली भारत, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत का श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उदय हो रहा है। पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है। रूस जैसा देश हमारे प्रधानमंत्री को सम्मानित कर रहा है। — **शिवराज सिंह चौहान**

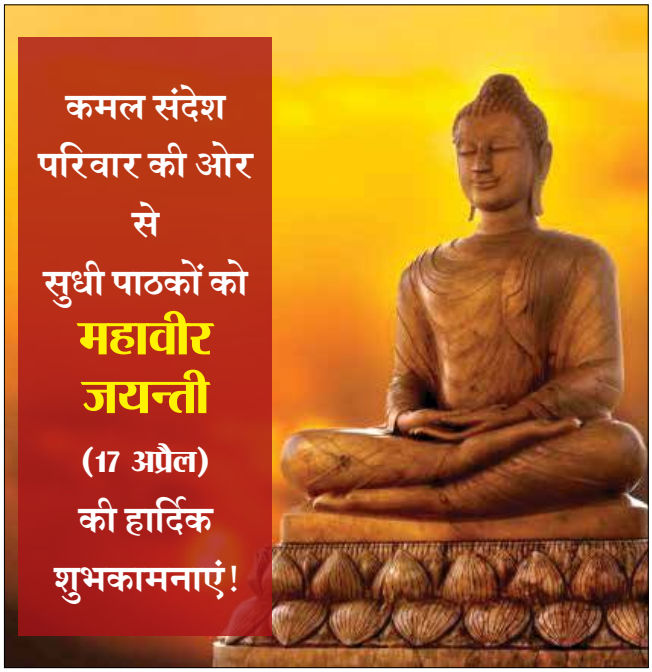

भविष्योन्मुखी - पथ को प्रशस्त करता भाजपा संकल्प पत्र

लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जारी भाजपा संकल्प पत्र राष्ट्र के तात्कालिक चुनौतियों के समाधान ढूंढने के साथ–साथ नए भारत के लिए एक सुदृढ़ नींव के निर्माण की भविष्योन्मुखी पथ को प्रशस्त कर रहा है। संकल्प पत्र जो 'भारत के मन की बात' कार्यक्रम के अंतर्गत भारी जनभागीदारी का परिणाम है, देश के तीव्र विकास एवं प्रगति के लिये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। यह एक बहु–स्तरीय एवं बहुआयामी एवं व्यापक जन–भागीदारी का परिणाम ही है जो एक 'संकल्पित एवं सशक्त भारत' के निर्माण के लिए एक संपूर्ण कार्ययोजना को अपने में समाहित किए हुए है। इसमें समाज के हर वर्ग का कल्याण, हर क्षेत्र की आवश्यकताओं और हर चुनौतियों को पूरे आत्मविश्वास एवं दृढ़ता से सामना करने का मंत्र है। वास्तव में यह एक आत्मविश्वास से भरे भारत जो गौरवशाली भविष्य के आलिंगन को तैयार है, उसका संकल्प पत्र है।

आज जबकि भाजपा पुनः सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, संकल्प पत्र उस निरंतरता पर बल देती है, जिसमें पिछले पांच वर्षों में हर क्षेत्र में जबरदस्त उपलब्धियां प्राप्त की और आने वाले पांच वर्षों में इन उपलब्धियों को आगे ले जाना चाहती हो। आज जबकि भारत विश्व की सबसे तेज गति से विकास करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुकी है, जिसने अपनी मुद्रास्फीति एवं बजटीय घाटे को नियंत्रित कर लिया है, भारत को कड़ी मेहनत से प्राप्त इन बढ़तों पर एक सुदृढ़ भविष्य का निर्माण करना हैं। संस्थागत सुधार, अभिनव प्रयोग, शासन में तकनीक की उपयोगिता में हुए प्रगति से अर्थव्यवस्था में वह स्थिरता आई है, जिससे अब वह एक लंबी छलांग लगाने को तैयार है। इन सबके साथ–साथ अंत्योदय के सिद्धांत पर गरीब से गरीब का कल्याण, किसान, मजदूर, अनु.जाति, अनु.ज.जाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के गरीब, महिला, युवा एवं छोटे उद्यमियों की हित में किये गय व्यापक कार्य पूरी अर्थव्यवस्था को बड़े लाभ पहुंचा रही है। महंगाई पर लगाम, कर में ब्याज पर कमी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, पारदर्शी एवं भागीदारीयुक्त शासन से समाज का हर व्यक्ति लाभान्वित है और सशक्त होकर अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। वास्तव में यदि देखा जाये तो यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि पिछले पांच वर्षों की कड़ी मेहनत से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को उस स्थान पर पहुंचा दिया है कि जहां से देश के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है।

जहां भाजपा संकल्प पत्र 'राष्ट्र प्रथम' के मंत्र से अभिमंत्रित है, वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र 'वोट बैंक प्रथम' के आधार पर जारी किया है। भाजपा ने पुनः समान नागरिक संहिता, राम मंदिर, धारा 370 एवं राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सम्मान से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है।

संकल्प पत्र पिछले पांच वर्ष की उपलब्धियों पर भविष्योन्मुखी निर्माण के लक्ष्य प्राप्ति का उद्घोष है। इसमें वर्णित 75 संकल्प जो 2022 में देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर पूरा करना है, एक समृद्ध एवं सशक्त भारत की कल्पना को साकार करने की भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, 2047 में जब देश अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनायेगा, उसके लिये अगले पांच वर्षों में मजबूत नींव डालने का संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी एवं दृढ़निश्चयी नेतृत्व को दर्शाता है। एक ऐसे भारत का स्वप्न देखना जिसमें हर किसी का अपना पक्का घर हो, सभी घरों में बिजली हो, पाइप से पीने का पानी पहुंचता हो, हर रसोईघर में गैस चूल्हा हो, घर में शौचालय हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य रक्षण हो– इन सब संकल्पों से सर्वस्पर्शी एवं सर्वव्यापी दृष्टि का पता चलता है जो 'सबका साथ, सबका विकास' की अवधारणा से प्रेरित है। संकल्प पत्र पूरे राष्ट्र के लिए एक विकासोन्मुखी परिवर्तनकारी कार्यक्रम को लेकर आया है।

जहां भाजपा संकल्प पत्र 'राष्ट्र प्रथम' के मंत्र से अभिमंत्रित है, वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र 'वोट बैंक प्रथम' के आधार पर जारी किया है। भाजपा ने पुनः समान नागरिक संहिता, राम मंदिर, धारा 370 एवं राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सम्मान से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है। इसके ठीक उलट कांग्रेस राष्ट्रीय संरचना को कमजोर करने वाले अलगाववादी एवं विध्वंसकारी तत्वों को अपने घोषणापत्र में बढ़ावा देने की बात करती है। भाजपा आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के लिए प्रतिबद्ध है पर कांग्रेस 'आफस्पा' एवं 'राष्ट्रद्रोह कानून' को ही मिटाना चाहती है और जब कांग्रेस गरीबों के कल्याण की बात करती है तब काफी हास्यास्पद लगता है। कांग्रेस जिसकी विश्वसनीयता अब नकारात्मक हो चुकी है अपने झूठे वादों से जनता को मूर्ख नहीं बना सकती। झूठ एवं फरेब की राजनीति में उलझने के स्थान पर कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। आज जब भारत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई एवं सुदृढ़ नेतृत्व में तेज गति से आगे बढ़ रहा है, संकल्प पत्र आने वाले सुनहरे भविष्य की झलकियां दिखा रहा हैं इससे निरंतरता, सुरक्षा, आत्मविश्वास, समृद्धि एवं प्रगति सुनिश्चित होगी। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

संकल्पित भारत, सशक्त भारत

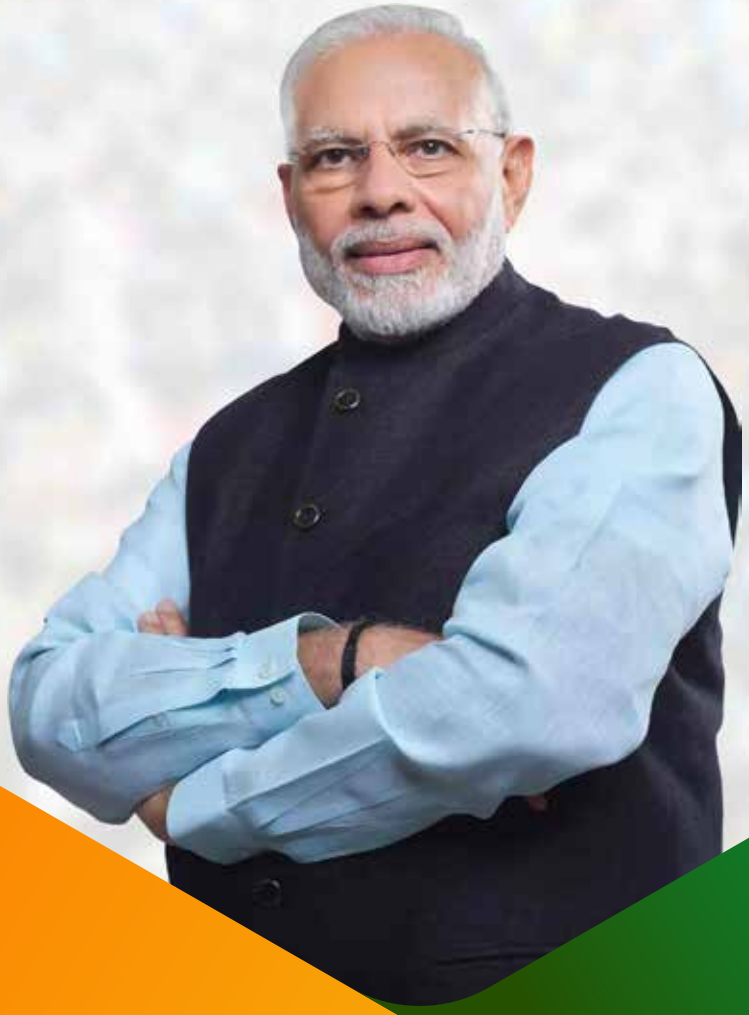

लोकसभा चुनाव हेतु भाजपा 'संकल्प पत्र' जारी

देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, भाजपा की संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष एवं देश के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल ने 8 अप्रैल, 2019 को पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में 'आम चुनाव 2019' के लिए भारतीय जनता पार्टी का 'संकल्प पत्र' जारी किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय पदाधिकारी और भारी संख्या में आम जनता एवं पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

"संकल्प पत्र" जारी करने के पश्चात् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा दर्शन है और सुशासन हमारा मंत्र है। उन्होंने कहा कि हमारे "संकल्प पत्र" का मूल मंत्र है - देश के विकास के लिए One Mission, One Direction और हम इसी प्रतिबद्धता के साथ देश के लिए समर्पित हो कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमने आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शासन चलाया, अब हम आमजन की आकाक्षांओं को लेकर हम क्या कर सकते हैं, हमने उसे अपने 'संकल्प पत्र' में शामिल किया है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत का विकास करने के लिए विकास को जन आंदोलन बनाने की जरुरत है और इसका सफल प्रयोग 'स्वच्छता' है। आज स्वच्छता एक जन आंदोलन बन गई है। Good Governance, Easy Governance, Transparent Governance, Responsible Governance... इन सारी बातों को बल देते हुए शासन व्यवस्था में हमने कई reforms किए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर गरीबी से लड़ना है तो ये समझना होगा कि दिल्ली के एयर कंडीशन कमरे में बैठे लोग गरीबी को परास्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि गरीब ही गरीबी को परास्त कर सकता है, यह हमारा मंत्र है। हम सुनते है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। अगर 21वीं सदी एशिया की सदी है तो भारत को उसका नेतृत्व करना चाहिए। हमने संकल्प पत्र में बताया है कि 2047 में जब देश आजादी की 100वीं वर्षगाठ मनाए तब भारत developing country से developed country की ऊंचाई को छूए। हमारा संकल्प पत्र, सुशासन पत्र भी है। हमारा संकल्प पत्र, राष्ट्र की सुरक्षा का पत्र भी है। हमारा संकल्प पत्र, राष्ट्र की समृद्धि का पत्र भी है।

इससे पहले संकल्प पत्र की प्रस्तावना रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमने भारत के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के लगभग 6 करोड़ लोगों के साथ संपर्क किया। इसके अतिरिक्त व्हाट्सअप, सोशल मीडिया और वेबसाइट के माध्यम से भी सुझाव हम तक आये, जिसके आधार पर हमने अपना संकल्प पत्र तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 की भारत की विकास यात्रा को देश के स्वर्णिम काल के तौर पर याद किया जायेगा, जबकि इससे पहले के 10 सालों (2004-2013) की

संकल्प पत्र की घोषणा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 से 2019 में हमारे कार्यों में सामान्य लोगों की जरूरतें हैं उन्हें हमने एड्रेस किया। देश जिन सपनों के साथ चल पड़ा है। जो 1950–60 के कालखंड में होना था वो मुझे 14 से 19 में करना पड़ा। पहले हमने जरूतरों को पूरा करने के लिए योजनाएं चलाई और अब देश के सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। गरीबी से लड़ना है तो दिल्ली में एसी में बैठे लोग गरीबी को परास्त नहीं कर सकते। मैं भी एसी में बैठता हूं इसलिए ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। गरीब ही गरीबी को खत्म कर सकता है।

– नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

संकल्प–पत्र जारी होने से पहले अमित शाह ने कहा– 2014 से 2019 की यात्रा का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब यह पांच साल स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने पड़ेंगे। इन पांच सालों में भाजपा ने एक निर्णायक सरकार देने का काम किया गया। 50 करोड़ गरीबों को उठाने के लिए काम हुआ है। मोदीजी की सरकार ने जरूरतमंदों तक गैस सिलेंडर, बिजली, घर, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का सफल प्रयास किया। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी दुनिया को सोचना पड़े ऐसा काम मोदी सरकार ने किया है। हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में ग्यारहवें नंबर पर थी।

– अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार में आये दिन घोटालों के कारण देश की छवि धूमिल हो रही थी और वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका नहीं के बराबर रह गई थी। विगत पांच वर्षों में एक भी घोटाले का आरोप भी मोदी सरकार पर नहीं लग पाया, इस प्रकार की प्रमाणिक सरकार भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में चलाई है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 70 सालों में पहली बार देश के लगभग 50 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का प्रयास कर गरीबों को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 11 वें स्थान पर थी जो 2019 में अब 6वें स्थान पर है और जल्द ही भारत पांचवें स्थान पर होगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की जड़ पर हमले की नीति श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने अपनाई जो पहले कभी नहीं हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दुनिया भर में संदेश गया है कि भारत अब कमजोर देश नहीं है, भारत की सीमा पर कोई अतिक्रमण नहीं सकता है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आज देश महाशक्ति बनकर उभरा है और यही पहचान भारत की अब बनी है। 70 साल की आजादी में भारत की कोई अंतरराष्ट्रीय भूमिका नहीं थी, लेकिन अब भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि कई सरकारें 30 साल में 4-5 बड़े काम कर पाती हैं, लेकिन मोदी सरकार ने पांच साल में 50 ऐसे काम किये हैं जो ऐतिहासिक हैं। यह किसी भी सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार ने निर्णायक लड़ाई लड़ी है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में चली विकास यात्रा, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई, वैश्विक मंचों पर भारत की निर्णायक भूमिका और देश के 50 करोड़ लोगों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने के प्रयासों से देश के सवा सौ करोड़ लोगों की आशा अब अपेक्षा में बदल गई है। उन्हें अब इस बात का विश्वास है कि श्री मोदी जी के नेतृत्व में "न्यू इंडिया" देश के हर नागरिक की अपेक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि 2022 में आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, हम सभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशवासियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए पचहत्तर संकल्पों का संदेश लेकर जाएंगे और उन्हें 2022 तक पूरा किया जायेगा।

श्री शाह ने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और जगन्नाथ पुरी से लेकर द्वारकाधीश तक देश के कोने-कोने से एक ही आवाज सुनाई देती है - मोदी, मोदी, मोदी। देश की जनता केंद्र में 'फिर एक बार, मोदी सरकार' बनाने का संकल्प ले चुकी है। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों में जनता की अपेक्षा के अनुरूप सरकार चलाई है। हम पुनः देश की जनता से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत, निर्णायक, पारदर्शी और निर्णायक सरकार देने का वादा करते हैं।

संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर संकल्प पत्र की प्रमुख बातों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के लगभग 6 करोड़ लोगों के सुझावों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को तैयार किया गया है, जो हमारे नए भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम 130 करोड़ भारतीय के सामने विजन डॉक्युमेंट को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें देश के सभी वर्गों, सभी लोगों की राय आधार पर ये दस्तावेज तैयार किया है। उन्होंने कहा कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और भाजपा नीत एनडीए सरकार में जनता का विश्वास बढ़ा है। विकास का चक्का अब तेजी से चलना आरंभ हुआ है। देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। ये सब करते हुए हमने जवाबदेही वाली सरकार बनाई है। जनभागीदारी को पूरी तरह से सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा

भारत के मन की बात इस संकल्प–पत्र में समाहित की गई है। हमारी सरकार ने जनता की हिस्सेदारी को संकल्प पत्र का अहम हिस्सा माना है और गरीब छह करोड़ लोगों से इस अपने संकल्प पत्र को लेकर बात की।
– राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री

भाजपा का 'संकल्प पत्र' 'टुकड़े–टुकड़े' मानसिकता के आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद की दृष्टि से तैयार किया गया है। यह पार्टी का संकल्प पत्र है जिसकी जड़ें वास्तविकता में हैं।
– अरुण जेटली, केंद्रीय वित्तमंत्री

भाजपा ने अन्य दलों की तरह घोषणा पत्र नहीं, बल्कि संकल्प पत्र जारी किया है। देश भाजपा पर भरोसा करता है कि इसकी सरकार ने 2014 में किए गए वादों से कहीं अधिक दिया है।
– सुषमा स्वराज, केंद्रीय विदेश मंत्री

कि ये भारतीय जनता पार्टी का 'संकल्प पत्र' नहीं, बल्कि एक विजन डॉक्युमेंट है जो बदलते भारत का परिचायक है। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव होते हैं, राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं। पहले जो भी वादे अन्य पार्टियों ने किए, वे थोड़े भी पूरे हो गए होते तो भारत आज बहुत आगे होता।

इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि हमने 2014 के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया है। अभी जो हमारा संकल्प पत्र है, वह 'टुकड़े-टुकडे गैंग' की सोच वाला नहीं है, बल्कि मजबूत राष्ट्रवादी सोच से तैयार किया गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में अनिर्णायक माहौल था और मजबूर सरकार थी। तब भाजपा और हमारे उम्मीदवार नरेंद्र मोदी लोगों के बीच आशा की एक नई किरण की तरह आए। आज माहौल बदल चुका है। उन्होंने कहा कि हम अकादमिक संस्थानों को उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहित करेंगे और इस तरह के संस्थानों को दुनिया के शीर्ष 500 संस्थानों में रैंक करने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि एक नया सुरक्षा सिद्धांत भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक बनाता है। उन्होंने कहा कि हम प्रभावी शासन और पारदर्शी निर्णय द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि हम घोषणाएं करने वाली सरकार नहीं, डिलीवर करने वाली सरकार बने हैं।

इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि बाकी सभी पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी किया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संकल्प पत्र लेकर आई है। उन्होंने कहा कि हम घोषणाएं करने नहीं आए हैं, इन संकल्पों को पूरा करने का व्रत लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि देश हम पर भरोसा इसलिए करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2014 के वादों से भी ज्यादा करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ 'गरीब हटाओ' का नारा दिया, लेकिन गरीब को गरीब ही बनाए रखा जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने गरीबों को सशक्त बनाने का प्रयास किया है। ■

130 करोड़ देशवासियों के सपनों का नया भारत

मेरे प्यारे देशवासियों,

भाजपा एक बार फिर आपके पास आई है ताकि आपका आशीर्वाद लेकर भारत की इस विकास यात्र को अबाधित, बिना थके, बिना रुके, एक नए उत्साह और उमंग के साथ जारी रख सके।

पांच साल पहले, 26 मई 2014 को ऐतिहासिक जनादेश मिलने के बाद भारत के सर्वांगीण विकास के इस संकल्प के साथय यात्रा शुरु की थी।

उस समय, भारत के समक्ष कई बड़ी चुनौतियां थीं– हमारी अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में थी तथा चारों ओर निराशा का वातावरण था। भ्रष्टाचार विकराल रूप ले चुका था। अपने नागरिकों के सपनों और आकांक्षाओं को पूटा कर पाने में भारत की क्षमता पर संदेह व्यक्त किया जा था।

लेकिन अगर चुनौतियां बड़ी थीं तो एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बनाने का हमारा संकल्प भी मजबूत था। 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और उनके कौशल के बलबूते अभूतपूर्व रूप से जन भागीदारी के साथ हमने अररोधों को अवसरों में अवनति को विकास की गति में और निराशा को आशा में बदला।

जो चीजें कभी नामुमकिन लगती थीं, उसको हमने तेज गति के साथ धरातल पर उतारा। पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक भारतीय परिवार को जन–धन योजना के कारण बैंक खाता मिला, 50 करोड़ भारतीयों को आयुष्मान भारत की बदौलत बीमारी से लड़ने का हौसला मिला और असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ से अधिक लोग अब पेंशन का लाभ ले सकते हैं।

स्वच्छ भारत अभियान ने जन आंदोलन का रूप ले लिया और पांच सालों में स्वच्छता का दायरा 38 प्रतिशत से बढ़कर आज 99 प्रतिशत के करीब पहुंच गया है। मुद्रा योजना के कारण अब छोटे शहरों के युवाओं के लिए उद्यमी बनना संभव हुआ है। 5 लाख रुपये तक की आय वाले नवमध्यम और मध्यमवर्ग के लोगों को अब आयकर से छूट मिल गई है।

हमारी सरकार ने भविष्य की सोच के साथ, तेजी से इनफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर किया है। सड़कों और रेलवे लाइनों के निर्माण की गति दोगुनी हो गई है। भारत के पास अब और भी अधिक अच्छे और आधुनिक बंदरगाह हैं। 2014 तक अंधेरे में रहने वाले 18,000 गांव अब ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रयासों से प्रकाशमान हो गए हैं। सौभाग्य योजना के माध्यम से 2.6 करोड़ से अधिक घरों को रोशन किया गया है। पिछले पांच वर्षों में बने 1.5 करोड़ घरों ने लाखों लोगों को बड़े सपने देखने की आजादी दी है। पिछले पांच साल का हमारा कार्यकाल साक्षी है कि कैसे देश की विकास यात्रा एक जन आंदोलन का रूप ले सकती है।

हमारा राष्ट्र अब निर्दयी आतंकी ताकतों के सामने लाचार नहीं है। देश की शांति और एकता के माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली हर विनाशकारी विचारधारा को करारा जवाब दिया गया है। उन्हें पहली बार सूद समेत उन्हीं के भाषा में कड़ा जवाब मिला है।

पूर्वोत्तर भारत जो अब तक अलग–थलग रहता था, में आज अभूतपूर्व विकास हो रहा है। पूर्वोत्तर आज देश की मुख्यधारा से मजबूती के साथ जुड़ गया है।

केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है। सत्ता के गलियारों में बिचौलियों की मौजूदगी इतिहास बन चुकी है। अब फैसले कुछ चुनिंदा लोगों के निजी स्वार्थ के बजाए सभी भारतीयों के सार्वजनिक हित से प्रेरित होकर लिए जाते हैं। जन–धन, आधार और मोबाइल की तिकड़ी ने 8 लाख से अधिक फर्जी लाभार्थियों की पहचान मे सहायता की है और 1 लाख करोड़ से अधिक रुपये की चोरी को रोका है। काले धन को सफेद करने से रोकने के लिए व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। भ्रष्टाचारियों में आज डर है।

आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ा है। विदेशी निवेश में रिकॉर्ड वृद्धि से यह स्पष्ट है कि दुनिया भारत की अपार क्षमताओं से

परिचित हुई है। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और हवाला की रोकथाम जैसे विषयों पर भारत के रुख ने इन्हें वैश्विक मुद्दा बना दिया है।

साथियों,

''संकल्पित भारत, सशक्त भारत'' इस पत्र में आपको पिछले पांच सालों में जिन चुनौतियों को देश ने परास्त किया है उनके बारे में उनसे निपटने के लिए 130 करोड़ भारतीयों द्वारा किए गए अदम्य प्रयासों के बारे में और आने वाले कल के लिए हमारे सामूहिक संकल्प की झलक मिलेगी।

पिछले पांच वर्षों में हमने बहुत कुछ हासिल किया है और आगे हम विकास की गति और विस्तार को एक नया आयाम देने के लिए संकल्पित है। ऐसे दो संकल्प हैं जो मेरे हृदय के बेहद करीब है– 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना और सबको घर। मुझे विश्वास है कि आपके समर्थन से यह अवश्य संभव होगा।

मैं भारत के लाखों जागरुक, प्रतिबद्ध और देशभक्त नागरिकों का धन्यवाद करता हूं, जिनके मूल्यवान सहयोग से यह ''संकल्पित भारत, सशक्त भारत'' पत्र तैयार हो पाया है और सही मायनों में लोगों की आवाज बन पाया है।

एक मजबूत और निर्णायक सरकार के लिए 2014 में आपके वोट ने हमें पांच वर्षों की छोटी सी अवधि में पांच दशकों के वंशवादी शासन की बुराइयों को दूर करने में सक्षम बनाया। अब जब इन बुराइयों पर हम विजय पा चुके हैं, तो उस गति की कल्पना करें जिसके साथ हम आने वाले समय में काम कर सकते हैं।

अगले पांच साल अहम हैं क्योंकि 2022 में हम अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनायेंगे। इस देश के महान सपूतों ने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, ताकि हम आजादी की खुली हवा में सांस ले सकें। उनके सपनों का भारत बनाना, आज हम में से प्रत्येक का दायित्व है।

2047 में, हमारा राष्ट्र स्वतंत्रता के सौ साल पूरे करेगा। आइए हम सब मिल कर सोच-विचार करें कि 2047 तक हम कैसा भारत चाहते हैं। भाजपा अगले पांच वर्षों में 2047 के भारत की नींव रखने की प्रतिज्ञा करती है। आइए, अब हम सब मिलकर इस संकल्प को पूरा करने में जुट जाएं।

विभिन्न राजनीतिक दलों और विचारधाराओं की कार्य संस्कृति और काम को देखने के बाद आज भारत के लोग आश्वस्त हैं कि अगर कोई पार्टी है जो देश की समस्याओं का समाधान कर सकती है, तो वह भाजपा है। 'सबका साथ, सबका विकास' का मंत्र भारत के कोने कोने तक गूंजा है। भाजपा हर भारतीय की पार्टी है। यह ऐसी पार्टी है, जो जमीनी स्तर पर 24 घंटे काम करती है। इसीलिए, हमें जो जनता का स्नेह और समर्थन मिला है, वह ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है।

नया भारत अतीत की बेड़ियों से आजाद हो चुका है। आज हमारा देश बड़े सपने देखने की हिम्मत भी करता है और उन्हें पूरा करने का जज्बा भी रखता है।

आइए हम सब मिलकर एक मजबूत और सर्वसमावेसी भारत के निर्माण की दिशा में काम करें, जहां हर भारतीय का सम्मान, समृद्धि, सुरक्षा और आगे बढ़ने के अवसर सुनिश्चित हों।

वन्दे मातरम!

नरेन्द्र मोदी

कांग्रेस का घोषणा-पत्र देश की सुरक्षा पर प्रहार : अमित शाह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का लोक सभा चुनाव 2019 के लिए जारी घोषणापत्र झूठ का पुलिंदा है और देश की जनता एवं जांबाज सिपाहियों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र के माध्यम से देश की सुरक्षा पर क्रूरतम प्रहार किया है।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में कहा है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर अफस्पा को कमजोर किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि अफस्पा को कमजोर करके वह सेना के मनोबल को बढ़ाना चाहती है या गिराना चाहती है। अफस्पा को कमजोर बनाकर कांग्रेस अध्यक्ष क्या संदेश देना चाहते हैं?

देश में जम्मू-कश्मीर समस्या की जनक कांग्रेस ही रही है। यह कांग्रेस पार्टी है जिसने जम्मू-कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देते हुए गैर संवैधानिक तरीके से धारा 35ए को देश पर थोपा। अब कांग्रेस पार्टी देशद्रोह के क़ानून को ख़त्म करके और अफस्पा को कमजोर करके आतंकवादियों और अलगाववादियों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। कांग्रेस पार्टी ने कश्मीरी पंडितों को अनदेखा करते हुए अपने पूरे घोषणापत्र में इस बारे में कोई जिक्र नहीं है। कश्मीरी पंडितों और उनके घाटी से पूरी तरह सफाये के बारे में घोषणा पत्र में पूरी तरह से चुप्पी है। कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में देशद्रोह के कानून को खत्म करने का वादा किया है। इसका मतलब कांग्रेस राज में 'भारत माता की जय' के बदले देशद्रोही गैंग के 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' के नारे लगेंगे। अफस्पा हटाने का मतलब यह है कि सेना के पास से आतंकवादियों पर प्रहार करने का हथियार छीन लिए जायेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि वह अलगाववादियों से बात करेगी। किसको

खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है? क्या कारण है कि आतंकवादियों, अलगावादियों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और कांग्रेस का घोषणापत्र एक ही भाषा का प्रयोग करता है?

कांग्रेस के साथी उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर में अलग से प्रधानमंत्री की मांग की है। कांग्रेस जवाब दे कि एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? क्या जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि वह उमर अब्दुल्ला के बयान के साथ है या नहीं? उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता।

कांग्रेस पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में कहा है कि सबको बेल मिल जाना चाहिए चाहे कोई भी अपराध हो, शायद कार्ति चिदंबरम को जेल से बचाने के लिए ही कांग्रेस पार्टी ने इसे अपने मेनिफेस्टो में शामिल किया है।

कांग्रेस पार्टी ने केवल जनता को गुमराह कर वोट हड़पने के लिए अब तक के सबसे बड़े झूठे वादे 'न्याय' का प्रचार किया, लेकिन मेनिफेस्टो में राहुल गांधी के इस महाजुमले की भी हवा निकल गई है। कांग्रेस ने मेनिफेस्टो में कहा है कि फिस्कल डेफिसिट को काबू में रखते हुए इसे लागू किया जाएगा। पहले एक कमिटी बनाई जायेगी फिर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना को शुरू किया जाएगा और फिर इसे कई चरणों में लागू किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस योजना के लिए धन कहां से आयेगा, इस पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अर्थव्यवस्था के विस्तार से और नए राजस्व स्रोतों से पैसा आयेगा। कांग्रेस अब यह भी कह रही है कि इस योजना को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लागू करेंगे। कई राज्य सरकारें यह दावा कर सकती हैं कि उनकी योजनाओं में कांग्रेस पार्टी के वादे से ज्यादा पैसा राज्य की जनता को दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में इसका भी उल्लेख किया है कि वर्तमान में चल रही जिन योजनाओं में मेरिट होगा, वही योजनायें चलती रहेंगी अर्थात् यह कि कांग्रेस कुछ योजनाओं को ख़त्म कर सकती है। इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस पार्टी एक हवा-हवाई योजना के जरिये फिर एक बार जनता के साथ विश्वासघात करने वाली है। देश की जनता को इससे सतर्क रहने की जरूरत है।

कांग्रेस ने कोई पहली बार झूठे वादे नहीं किये हैं। कांग्रेस पार्टी का झूठे वादे करने का एक लंबा इतिहास रहा है। आज तक कांग्रेस ने एक भी वादा अपने कार्यकाल में पूरा करके नहीं दिखाया।

कांग्रेस ने 2004 के घोषणापत्र में बिजली पहुंचाने का वादा किया था। 2009 और 2014 में भी यह कांग्रेस के घोषणापत्र का हिस्सा रहा, लेकिन इसे पूरा मोदी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में किया। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि वह किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए फीजिबिलिटी को एक्जामिन करेगी। कांग्रेस ने इसी तरह के वादे 2004, 2009 और 2014 में भी किये थे और अब 2019 में भी कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है जबकि मोदी सरकार ने देश के 12 करोड़ से अधिक किसानों को 6000 रुपये देने की शुरुआत कर भी चुकी है। OROP 40 साल से पेंडिंग था। कांग्रेस ने 2004 के घोषणापत्र में इसे लागू करने का वादा किया था। वह 10 साल में इसे पूरा नहीं कर पाई, इसके लिए सरकार जाते समय कांग्रेस पार्टी ने केवल 500 करोड़ रुपये आवंटित किये थे। मोदी सरकार ने एक साल में ही OROP लागू किया और अब तक सैनिकों के खाते में लगभग 35,000 करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई भी जा चुकी है। 2004 में कांग्रेस ने वादा किया था कि वह जनता के प्रति जवाबदेह है, इसलिए हर साल 2 अक्टूबर को पूरे किए गये वादों का लेखा जोखा जनता के सामने रखेगी। कांग्रेस ने यह भी वादा किया था कि सरकार बनने के 100 दिनों में वह एक्शन प्लान पेश करेगी। आज तक कांग्रेस की सरकार में यह हुआ ही नहीं। मोदी जी हर साल अपने कामकाज का लेखा-जोखा देश की जनता को देते हैं।

कांग्रेस पार्टी ने 2011 तक देश के हर नागरिक को आधार कार्ड देने का वादा किया था, सरकार जाने तक कांग्रेस पार्टी केवल 46 करोड़ लोगों को ही आधार कार्ड से जोड़ पाई थी। आज देश के लगभग हर नागरिक के पास आधार कार्ड है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि वह सुरक्षा जरूरतों के लिए हाइएस्ट लेवल के कदम उठायेगी। रहने दीजिये राहुल बाबा, आप 10 साल में एक लड़ाकू विमान का डील तो कर नहीं पाए। कांग्रेस ने वादा किया है कि वह सबको स्वास्थ्य सुरक्षा देगी। वास्तविकता यह है कि 2013-14 तक केवल ढाई करोड़ लोग ही इस योजना से कवर्ड हो पाए थे। मोदी जी ने देश के 50 करोड़ गरीबों को पांच लाख रुपये तक की वार्षिक स्वास्थ्य बीमा दे दी है। पिछले चार महीनों में ही 20 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो पाए हैं। कांग्रेस ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को लेकर कहा है कि तीन वर्षों में हम हर गांव को इससे जोड़ेंगे। सच्चाई यह है कि 2014 में देश के ढाई लाख ग्राम पंचायतों में से केवल 59 ग्राम पंचायत ही ब्रॉडबैंड से जुड़ पाए थे। आज मोदी सरकार के पांच वर्षों में 1.16 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछा दिया गया है। ■

संकल्प पत्र में हैं ये खास बातें :

राष्ट्र सर्वप्रथम

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व ने पिछले पांच वर्षों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इसी नीति पर हम आगे बढ़ेंगे।

आतंकवाद पर सुरक्षा नीति

हमारी सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी। इसके उदाहरण हाल ही में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हैं। हम आतंकवाद एवं उग्रवाद के विरुद्ध "जीरो टॉलरेंस" की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे और सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए 'फ्री हैंड' की नीति का अनुसरण करते रहेंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा

अपने सुरक्षा बलों को सुदृढ़ बनाएंगे- हम रक्षा से जुड़े बाकी उपकरणों एवं हथियारों की खरीद तेज करेंगे। सुरक्षा बलों की हमला करने की क्षमता सुदृढ़ बनाने हेतु सैन्य बलों को आधुनिक उपकरण प्रदान करने के लिए हम सघन प्रयास जारी रखेंगे।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे- रक्षा उपकरणों की खरीद में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने पिछले पांच वर्ष में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। हमारी सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि सबसे आधुनिक एके-203 स्वचालित राइफल्स बनाने की फैक्ट्री की नींव रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' अभियान के अंतर्गत अमेठी में रखी गई है। हम 'रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया' को और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि रक्षा उपकरणों का स्वदेश में ही निर्माण हो सके। इससे रोजगार सृजन होगा और रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

सैनिकों का कल्याण

हमारी सरकार ने लंबे समय से लंबित 'वन रैंक वन पेंशन' को लागू कर सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के हितों के प्रति अपने संकल्प को प्रतिबद्धता से पूरा किया। इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के पुनर्वास के लिए अधिक प्रभावी ढांचा तैयार करने का वादा करते हैं। इस प्रयास के अंतर्गत सशस्त्र बल के सैनिकों के सेवानिवृत्त होने से तीन वर्ष पूर्व उनकी पसंद के अनुसार ही उनके पुनर्वास की योजना आरंभ कर देंगे। इसमें कौशल प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, आवास एवं उद्यम आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल होगा।

घुसपैठियों की समस्या का समाधान

घुसपैठ से कुछ क्षेत्रों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान में भारी परिवर्तन हुआ है और स्थानीय लोगों की आजीविका तथा रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिकता पर एन आर सी का कार्य किया जाएगा। देश में चरणबद्ध तरीके से चिन्हित करके इसे लागू करेंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में legal Immigration रोकने के लिए प्रभावी प्रयत्न किए जाएंगे। इसके लिए हम देश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे। सीमाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए तकनीक के प्रयोग (स्मार्ट फेसिंग) का पायलट प्रोजेक्ट धुबटी (असम) में लागू किया गया था, उसको हम सभी सीमाओं पर लागू करेंगे।

वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला

हमने वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध बहुत सख्त कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप इन उग्रवादियों का कार्य क्षेत्र सिमट कर रह गया है। अगले पांच वर्षों में हम इसके विरुद्ध और अधिक कारगर कदम उठाएंगे, जिससे कि अगले पांच वर्षों में इस खतरे को दूर करने में हम सफल हो सकें। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इस क्षेत्र में हमने विकास के कार्यों, जिसमें सड़क, मोबाइल फोन, स्कूल, चिकित्सा सेवा शामिल है, पांच वर्षों में बहुत प्रगति की है। हम इस कार्य को और ज्यादा गति से चलाएंगे, ताकि ये पिछड़े क्षेत्र भी इन सुविधाओं के लाभ से आगे आ सकें।

जम्मू-कश्मीर : धारा 370

पिछले पांच वर्षों में हमने निर्णायक कार्रवाई और एक दृढ़ नीति के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए हैं। राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने और राज्य के हर क्षेत्र के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम जनसंघ के समय से अनुच्छेद 370 के बारे में अपने दृष्टिकोण को दोहराते हैं।

हम धाटा 35A को भी खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मानना है कि धारा 35A जम्मू-कश्मीर के गैर-स्थायी निवासियों और महिलाओं के खिलाफ़ भेदभावपूर्ण है। यह धारा जम्मू कश्मीर के विकास में भी बाधा है। राज्य के सभी निवासियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हम सभी कदम उठाएंगे। हम कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेंगे।

किसानों की आय दोगुनी

भाजपा सरकार के वर्तमान कार्यकाल के प्रारंभ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने को मिशन के रुप में लिया। हम इस लक्ष्य को 2022 तक पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेंगे।

किसान कल्याण नीति

सभी के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना – हमने 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों के लिए आय सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' आरंभ की है। हम इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसे देश के सभी किसानों के लिए लागू करेंगे।

छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन– हम देश में सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन की योजना आरंभ करेंगे, जिससे कि 60 वर्ष की आयु के बाद उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश– हम कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने को प्रतिबद्ध हैं।

ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड ऋण – हम 1 से 5 वर्ष के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रुपए तक के नए अल्पावधि कृषि ऋण मूल राशि के समय पर भुगतान की शर्त पर प्रदान करेंगे।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्वैच्छिक पंजीकरण – 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' ने सुनिश्चित किया है कि किसानों के लिए जोखिम कम हो और उन्हें बीमा की सुरक्षा मिले। हम इस योजना के तहत किसानों के स्वैच्छिक पंजीकरण का प्रावधान करेंगे।

नीतियों के जरिए किसानों का सशक्तिकरण – हम कृषि आयात में कमी लाने और अनुमान-योग्य कृषि निर्यात एवं आयात नीति बनाने की दिशा में काम करेंगे, जिसमें कृषि उत्पादों के नियति को बढ़ावा देने तथा आयात को कम करने की एकीकृत व्यवस्था होगी।

5 ट्रिलियन डॉलर के अर्थव्यवस्था की रूपरेखा

सन 2014 में भारत को 'फ्रेजाइल फाइव' (पांच कमजोर देशों) में गिना गया था। पांच वर्ष के भीतर भारत ने एक ख्याति अर्जित की, जो न केवल विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बल्कि आर्थिक रुप से स्थिर भी है। हम विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पहले ही बन चुके हैं और जल्द ही शीर्ष पांच में शामिल हो जाएंगे। हम सन 2030 तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि हम सन 2025 तक भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर और सन 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लेते हैं।

मेक इन इंडिया

भारत को ज्ञान आधारित, कौशल समर्थित एवं तकनीक से चलने वाला समाज बनाने के लक्ष्य के साथ हमने 'मेक इन इंडिया' अभियान आरंभ किया है। हमनें डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसे नवाचारों के जरिए शुरुआत पहले ही कर दी है। तीव्र एवं समावेशी वृद्धि के लिए हमने पिछले कुछ वर्षों में विनियमन एवं लाइसेंस समाप्त करने जैसे महत्वपूर्ण सुधार भी किए हैं, जिनका लक्ष्य कारोबारी सुगमता (ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस) बढ़ाना है।

शहरी विकास को प्राथमिकता

इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास के जरिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उपनगरी बस्तियों और नए शहरी केंद्रों का विकास हो सके। हम शहरी मुद्दों पर उत्कृष्ट पांच स्थानीय केंद्र स्थापित करेंगे। इन केंद्रों के माध्यम से राज्यों एवं स्थानीय इकाइयों को भी शहरी सुशासन और विकास के मुद्दों पर सहयोग प्रदान करेंगे।

स्वच्छ भारत मिशन

हमने अपनी प्रमुख योजना 'स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 9 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया। अब हम अपने इस मिशन को नया आयाम देंगे और हर गांव में सतत ठोस कचरा प्रबंधन लागू करेंगे। हम हर गांव, उपनगर और बिना नालियों वाले क्षेत्रों में तरल अपशिष्ट के पूर्ण निस्तारण को मल-प्रबंधन और गंदे पानी के पुनः इस्तेमाल के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे।

हवाई अड्डे

2014 में देश में 65 कार्यात्मक हवाई अड्डे थे और आज कुल 101 कार्यात्मक हवाई अड्डे हैं। अगले पांच वर्षों में हम कार्यात्मक हवाई अड्डों की संख्या को दोगुना कर देंगे।

ऊर्जा

हमने सभी देशवासियों को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था और यह प्रसन्नता की बात है कि देश ने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है; शीघ्र बचे हुए सभी घरों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।

डिजिटल कनेक्टिविटी

2022 तक हर ग्राम पंचायत को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। गांवों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की जाएंगी; साथ ही टेली-मेडिसिन, टेली-एजुकेशन और कृषि आधारित परामर्श उपलब्ध करया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10.74 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, हमने 2022 तक 1,50,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने का कार्यक्रम बनाया है। वर्तमान में 17,150 केंद्र स्थापित हो चुके हैं और सफलतापूर्वक चल रहे हैं। अब हम इन केंद्रों की स्थापना के कार्यक्रम को और विस्तार देंगे। इसके साथ ही हम हर गरीब के दरवाजे पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन 2022 तक टेलिमेडिसिन के प्रावधानों और डायग्नॉस्टिक लैबोरेटरी सुविधाओं (diagnostic laboratory facilities) को लक्षित कर कार्य कर रहे हैं।

एक साथ चुनाव

खर्च घटाने, सरकारी संसाधनों एवं सुरक्षा बलों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने और प्रभावी नीति नियोजन के लिए हम संसद एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विचार का समर्थन करते हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इस विषय पर सभी पार्टियों के साथ सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।

भ्रष्टाचार मुक्त भारत

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 और बेनामी लेनदेन निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2016 लागू करने जैसे कई प्रभावी कदम उठाए हैं। हमने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निर्णायक कार्य सुनिश्चित कर सरकार में चल रही लालफीताशाही समाप्त कर दी है। हम अधिक प्रभावी प्रशासन एवं निर्णय लेने की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखेंगे।

युवाओं के लिए नए अवसरों में वृद्धि

भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले 22 उत्कृष्ट क्षेत्रों (चैंपियन सेक्टर्स) की पहचान कर, उन क्षेत्रों में निर्णायक नीतियों के माध्यम से रोजगार के नए अवसरों को पैदा करने का कार्य करेंगे। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखते हुए उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों जैसे रक्षा एवं फार्मास्युटिकल में रोजगार सृजन की दिशा में कार्य करेंगे।

उद्यमिता एवं स्टार्टअप- युवाओं में उद्यमशीलता की भावना को विकसित करने हेतु हम निम्नलिखित कदम उठाएंगे:

हम उद्यमियों के लिए 50 लाख तक के कोलेटरल मुक्त ऋण (कोलेटरल-फ्री क्रेडिट) के लिए एक नई योजना लायेंगे। हम महिला उद्यमियों के लिए ऋण राशि के 50% और पुरुष उद्यमियों के लिए ऋण राशि के 25% की गारंटी सुनिश्चित करेंगे।

हम उत्तर-पूर्वी राज्यों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देने और उत्तर पूर्व में रोजगार सृजन के लिए एक नई उद्यमशील उत्तर-पूर्व योजना लाएंगे।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पिछले पांच सालों में उद्यम क्षेत्र में नए अवसर पैदा करने के लिए 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऋण दिया गया। हम इस योजना का विस्तार करते हुए 30 करोड़ लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

हम 20,000 हजार करोड़ रुपए के 'सीड स्टार्टअप फंड' के जरिए स्टार्टअप्स को लगातार प्रोत्साहित करेंगे और बढ़ावा देते रहेंगे।

खेल

हम राज्य एवं जिला स्तर पर प्रतिभा और योग्यता के अनुसार खिलाड़ियों की पहचान करेंगे; साथ ही पारंपरिक खेलों को चिह्नित कर उनके खेल तथा क्षेत्र के आधार पर प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे।

हमने 'खेलो इंडिया' योजना से देश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं और हम इस योजना के तहत पर्याप्त संसाधन प्रदान करना जारी रखेंगे ताकि घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। योजना के तहत महिलाओं और आदिवासियों के बीच खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष ध्यान देंगे।

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा

स्कूली शिक्षा को सुलभ और सुदृढ़ बनाने के बाद अब हमारा ध्यान सीखने की गुणवत्ता पर है। हमने पहले ही कई कक्षाओं के लिए सीखने के प्रतिफलों की पहचान कर ली है और हमारी प्राथमिकता है कि अगले पांच सालों में सभी विद्यार्थी इन प्रतिफलों को अर्जित कर लें। इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर हमारा विशेष ध्यान है।

उच्च शिक्षा

केंद्रीय विधि, इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रबंधन संस्थानों में हम अगले पांच सालों में कम से कम 50 प्रतिशत तक सीट बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। हम राज्य सरकारों को भी राज्यों के संस्थानों में सीट बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे।

कौशल विकास

हम नई तकनीक और नए अवसरों के लिए तैयार उद्योग-अनुरुप कार्यक्षमता से लैस श्रमबल तैयार करने के लिए 'नेशनल रीस्किलिंग और अपस्किलिंग नीति' का निर्माण करेंगे।

महिला–प्रेरित विकास

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बेटियों को अबाधित शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। हम शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी बालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और उच्च शिक्षा ऋण में रियायत प्रदान करेंगे।

महिलाओं को समान अधिकार

हमने महिलाओं के संपूर्ण विकास और लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। हम तीन तलाक और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं के उन्मूलन और उन पर रोक लगाने के लिए एक कानून को पारित करेंगे।

महिलाओं को आरक्षण

सरकार के अंतर्गत तमाम स्तरों पर महिला कल्याण एवं विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। भाजपा संविधान में प्रावधान के जरिए संसद एवं राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सबके लिए न्याय

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सभी लोगों को संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध हर लाभ प्रदान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन वर्गों में शामिल हर व्यक्ति को सही प्रतिनिधित्व और समान व न्यायपूर्ण अवसर प्रदान किए जाएं।

हमने निर्णायक रुप से यह सुनिश्चित किया है कि गैर-आरक्षण वर्ग में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में उचित प्रतिनिधित्व तथा अवसर मिले, जिसके लिए हमने आर्थिक रूप से कमजोर गैर-आरक्षण वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया। हम इस प्रावधान को लागू करते हुए यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले।

गरीब कल्याण

अगले पांच वर्षों में हम गरीबी रेखा से नीचे मौजूद परिवारों के प्रतिशत को कम करते हुए एक अंक में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हम 2022 तक ऐसे प्रत्येक परिवार को पक्का मकान देंगे, जो कच्चे मकानों में रहते हैं।

हम खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए गरीब और कम आय वाले परिवारों के कुल 80 करोड़ लोगों को अनाज (गेहूं, चावल, मोटे अनाज) अधिकाधिक सब्सिडी पर उपलब्ध करवाने में सफल हुए हैं। इसे विस्तार देते हुए हम इन परिवारों को सब्सिडी पर चीनी (प्रति परिवार प्रति माह 13 रुपये प्रति किलो) उपलब्ध करवाएंगे, जो हमारे आदर्श वाक्य 'सबका साथ-सबका विकास' को चरितार्थ करता है।

अल्पसंख्यक वर्ग

सबका साथ-सबका विकास के संकल्प पर हम सभी अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी) के सशक्तिकरण हेतु और उन्हें गरिमापूर्ण विकास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

दिव्यांगों को सक्षम बनाना

'सुगम्य योजना के तहत नगरों, एयरपोर्टों, रेलवे स्टेशनों और जन आवागमन सुविधाओं तथा शहरी आधारभूत संरचना के नियमित ऑडिट और डेटिंग की व्यवस्था करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि दिव्यांग जनों को यह सुलभता से उपलब्ध हो। इसके लिए सिविल सोसाइटी से जुड़े संगठनों और उद्योगों की सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे।

ट्रांसजेंडर वर्ग का सशक्तिकरण

हम सामाजिक और नीति-निर्णायक स्तर पर सभी ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हम ट्रांसजेंडर वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार और कौशल विकास के अवसर सुनिश्चित करेंगे।

राम मंदिर

राम मंदिर पर भाजपा अपना रुख दोहराती है। संविधान के दायरे में अयोध्या में शीघ्र राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा और इसके लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।

योग: गौरवशाली विरासत का वैश्विक विस्तार

हम दुनिया भर में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रुप में मनाते हुए योग के प्रचार और विस्तार के क्षेत्र में अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखेंगे। हम योग को विश्व के लिए एक स्वच्छ जीवन पद्धति का प्रमुख माध्यम बनाएंगे और योग प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु नई पहल करेंगे। साथ ही, हम योग से संबंधित पर्यटन, स्वास्थ्य सुविधाएं और अनुसंधान के क्षेत्र का विस्तार करेंगे।

समान नागरिक संहिता

भारत के संविधान 44 में समान नागरिक संहिता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों के रूप में दर्ज की गई है। भाजपा का मानना है की जब तक भारत में समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता है, तब तक लैंगिक समानता कायम नहीं हो सकती है। समान नागरिक संहिता, सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है। भाजपा सर्वश्रेष्ठ परम्पराओं से प्रेरित समान नागरिक संहिता बनाने को कटिबद्ध है जिसमें उन परम्पराओं को आधुनिक समय की जरुरतों के मुताबिक ढाला जाये। ■

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गांधीनगर सीट से किया नामांकन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 30 मार्च को गुजरात के गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने से पहले श्री अमित शाह ने गांधीनगर में एनडीए में शामिल सहयोगी दलों के नेताओं के साथ चार किलोमीटर लंबा रोड शो किया।

रोड शो से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा, '1982 में मैं यहां बूथ कार्यकर्ता के रूप में नारनपुरा इलाके में पोस्टर और पर्चा चिपकाता था और आज पार्टी अध्यक्ष हूं। आज मेरे पास जो भी है, वह भाजपा की देन है। आज चुनाव केवल इस बात पर लड़ा जाएगा कि इस देश का नेतृत्व कौन करेगा। देश के कोने-कोने से मोदी-मोदी आवाज आ रही है। मोदीजी निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मैं गुजरात की जनता से अपील करना चाहता हूं कि गुजरात की सभी 26 सीटें नरेन्द्र मोदी को दे दीजिए और शान से प्रधानमंत्री बनाइए।'

यह रोड शो अहमदाबाद के नारनपुरा इलाके में सुबह सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू हुआ। 4 किलोमीटर लंबा यह रोड शो घाटलोदिया इलाके में पाटीदार चौक पर खत्म हुआ। इस रोड

शो में केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, शिरोमणि अकाली दल के नेता श्री प्रकाश सिंह बादल, एलजेपी के श्री रामविलास पासवान और शिवसेना प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे भी हिस्सा लिया।

रोड शो के बाद श्री अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। पाटीदार चौक से श्री अमित शाह नामांकन पत्र भरने अपनी कार से गांधीनगर गए। बता दें कि गुजरात की सभी 26 सीटों पर मतदान 23 अप्रैल को होगा। ■

'चौकीदार' एक स्पिरिट है, एक भावना है : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को दिल्ली के तालकटोरा मैदान से 'मैं भी चौकीदार' अभियान के तहत देश भर में 500 स्थानों पर लाखों लोगों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित किया और देश की विकास यात्रा में अवरोध उत्पन्न करने के लिए कांग्रेस पार्टी को कठघरे में खड़ा करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री देश के पांच सौ सेंटरों से सीधे जुड़े और उन्होंने देश के संसाधनों की रखवाली कर रहे विभिन्न वर्गों के लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विगत 16 मार्च को इस अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद देश भर के तमाम लोगों ने इस अभियान में भाग लेते हुए अपने नाम के आगे 'चौकीदार' शब्द जोड़ा था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में होने वाले आम चुनाव पर सबकी निगाहें होना स्वाभाविक है। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 2013-14 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तब मैं देश के लिए बिल्कुल नया था लेकिन मेरे आलोचकों ने ही ज्यादातर मेरा प्रचार किया। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उन्हीं के कारण मेरे लिए देश में जिज्ञासा पैदा हुई थी कि आखिर यह इंसान है कौन?

भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सरकार चलाने का दायित्व सौंपा, तब मैंने देशवासियों से कहा था कि आप दिल्ली का दायित्व जो मुझे दे रहे हैं उसका मतलब है कि आप दिल्ली में अपना एक चौकीदार बैठा रहे हैं। मैंने तब कहा था कि मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं जनता के पैसे पर पंजा नहीं पड़ने दूंगा। एक चौकीदार के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा।

श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सरकार चलाने का दायित्व सौंपा, तब मैंने देशवासियों से कहा था कि आप दिल्ली का दायित्व जो मुझे दे रहे हैं उसका मतलब है कि आप दिल्ली में अपना एक चौकीदार बैठा रहे हैं। मैंने तब कहा था कि मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं जनता के पैसे पर पंजा नहीं पड़ने दूंगा। एक चौकीदार के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा लेकिन कुछ लोगों की अपनी बौद्धिक सीमाएं होती हैं, इसलिए उनके मन में चौकीदार की सोच पारंपरिक होती है। यह उनकी सीमित सोच का परिणाम है कि वे चौकीदार का मजाक उड़ा रहे हैं। आज देश की जनता अपने चौकीदार को पसंद कर रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि चौकादार का भाव निरंतर विस्तार होता जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि चौकीदार की न कोई व्यवस्था है, न किसी यूनिफॉर्म की पहचान है। यह किसी चौखट में भी बंधा हुआ नहीं है। 'चौकीदार' एक स्पिरिट है, एक भावना है। गांधीजी कहते थे कि जो भी हमें दायित्व मिला है, जिन चीजों को हम संभालते हैं चाहे वो समय हो या व्यवस्था हो, हमें इसे एक ट्रस्टी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें संभालना चाहिए।

श्री मोदी ने कहा कि देश की जनता फिर से एक बार हमें देश की सेवा करने का मौका देने वाली है। मुझे खुशी है कि देश के युवा दूर की सोच कर चलते हैं। हम राजनेता तो अभी 11 अप्रैल को क्या होगा या 21 मई को क्या होगा, इसी में लगे पड़े हैं लेकिन देश की जनता तो शपथ के विषय में सोच रही है।

प्रधानमंत्री जी का जन–संवाद

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से अजय दबे का सवाल: बालाकोट में जो आपने किया वो गजब हुआ और सबका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ऐसा लग रहा है कि भारत ने सालों बाद अपना दम दिखाया। आपको यह फैसला लेने में प्रेरणा कहां से मिली? आपके मन में यह सोच नहीं आई कि अगर इस ऑपरेशन में गड़बड़ी हो जाती तो आपके राजनीतिक करियर का क्या होता?

जवाब: प्रधानमंत्री ने कहा कि बालाकोट मैंने नहीं, देश के जवानों और सुरक्षाबलों ने किया है। हम सबकी तरफ से उनको सैल्यूट। जहां तक निर्णय का सवाल है- अगर मोदी अपने राजनीतिक भविष्य का सोचता तो मोदी नहीं होता। अपने राजनीतिक हित और भलाई को नजर में रखकर फैसले करने होते तो मोदी की इस देश को कोई जरूरत नहीं होती। मोदी के लिए देश सबसे ऊपर है। सवा सौ करोड़ सबसे ऊपर हैं। मेरा अपना वैसै भी है क्या? आगे पीछे कोई चिंता नहीं रखी है।

श्री मोदी ने कहा कि राजनीति में मुझ जैसे अनजान व्यक्ति को जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार अपने आप में देश की बहुत बड़ी ताकत होती है। आज दुनिया में हिंदुस्तान की बात सुनाई देती है तो इसकी बहुत बड़ी वजह केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है। आज कोई नेता गले मिलता है, गले पड़ता नहीं है... (लोगों ने जम कर ठहाके लगे) तो उसे मोदी की नहीं पूर्ण बहुमत की

सरकार की ताकत दिखाई देती है।

श्री मोदी ने कहा कि यह निर्णय मैं इसलिए कर पाया, क्योंकि मुझे मेरी सेना पर भरोसा है। उन्हें छूट दे पाया क्योंकि मुझे उनके अनुशासन पर भरोसा है। मुझे पता है कि वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि मेरे देश को कभी नीचा देखना पड़े। इसलिए उनके हाथ में इतना बड़ा निर्णय देने की मेरे अंदर ताकत थी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से शकुंतला सिंह परिहार ने भ्रष्टाचार पर प्रश्न किया:

जवाब: प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने देश लूटा है उन्हें देश की जनता को पाई-पाई लौटानी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद से आपकी मदद से मैं इन लोगों को जेल के दरवाजे तक तो ले गया हूं। 2019 के बाद यह जेल के अंदर होंगे। यह जो भागते हैं न, उन्हें अब डर लग रहा है। कोई जमानत पर है, कोई अदालत के चक्कर काट रहा है। अब नए अफसरों की मदद से कागज भी हाथ लगने लगे हैं। कुछ लोग विदेश की अदालत में कहते हैं कि हम भारत की में रह नहीं सकते। हम उन्हें महल दें क्या? अरे, उन्हें बता दो कि अंग्रेजों ने गांधीजी को जिस जेल में रखा, उससे अच्छा हम इन्हें नहीं देंगे न।

बेंगलुरु से राकेश प्रसाद (आईटी प्रोफेशनल) का सवाल: सालों से हम सुन रहे हैं कि भारत विकासशील देश है? हम कब यह सुनेंगे कि भारत विकसित हो गया?

जवाब: प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बात सही है कि बहुत देर हो चुकी है। आजादी के बाद हमने देश के लिए कुछ कर गुजरने के उद्देश्य से देश को सही दिशा दी होती तो आज स्थिति कुछ दूसरी होती। हमसे बाद में आजाद हुए देश कहें बेहतर स्थिति में हैं। देश के सा सौ करोड़ लोगों का सपना होना चाहिए कि हमें बैकवर्ड की श्रेणी में नहीं आना।

श्री मोदी ने कहा कि 2014 में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 11वें नंबर पर थे। तब की सरकार इसी पर खुश हो रही थी, लेकिन पिछले पांच वर्षों में आज हम छठें स्थान पर आ गए हैं। हम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ऐसा हमने बिना कोई शोरगुल मचाए हुए किया है। हम दुनिया की समृद्ध शक्तियों के साथ जुड़े। हाल ही में हमारी अंतरिक्ष में ताकत बढ़ी। विकसित राष्ट्र के रूप में जगह पाने के लिए भारत के पास सब कुछ है, बस इच्छाशक्ति की कमी थी लेकिन अब भारत रुकने वाला नहीं है।

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से श्री रामसिंह राणावत का सवाल: मिशन शक्ति के बारे में कांग्रेस कह रही थी कि यह हम पहले कर चुके हैं और यह कोई नई बात नहीं है?

जवाब: प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि 'मिशन शक्ति' जैसी चीजें चुनाव के चश्मे से देखी जा रही है। हमसे पहले केवल तीन देशों अमेरिका, रूस और चीन ने यह काम किया था। ऐसा करने वाले दुनिया के चौथे देश हैं। मान लीजिए कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल कर हमारी सैटेलाइट गिरा दे, तो हमारी कई चीजें बंद हो जाएंगी। अब इसके लिए क्या वैज्ञानिकों को इंतजार करना चाहिए?

श्री मोदी ने कहा कि एक नेता ने कहा कि यह चीज हमारे पास बहुत पहले से थी, लेकिन हमने इसे दबाकर रखा। क्या ऐसा हो सकता है? जब अमेरिका, रूस, चीन ने इसे डंके की चोट पर किया तो हमें छुपना क्यों? अब जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हें 'साबु' का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी सामान्य बुद्धि। आप टेस्ट न करो, कहते रहो हमारे पास ताकत है। तो आखिर यह साबित कैसे होगी?

योगी आदित्यनाथ की ओर से आगरा से राजेश वाल्मिकी का प्रश्न: कांग्रेस रोजाना नए-नए झूठ **बोलती है, एक झूठ सौ-सौ बार** बोलती है। पिछले पांच सालों में उन्होंने झूठ ही बोला है। उनका झूठ बहुत मजबूत है, इसको हम कैसे एक्सपोज करें?

जवाब: प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का झूठ बड़ा सीजनल होता है। जैसे पतंगों का सीजन होता है, पटाखों का सीजन होता है। सीजन के हिसाब से वो झूठ बोलते हैं, फिर प्रचारित करते हैं। उनका झूठ का इकोसिस्टम है। उन्होंने दिल्ली में चुनाव के दौरान झूठ उड़ा दिया था कि चर्च पर हमले हो रहे हैं। बाद में यह पूरी तरह से झूठ निकली। बिहार में उन्होंने कहा था कि मोदी आ रहा है, आरक्षण चला जाएगा। संविधान खतरे में पड़ जाएगा। आरक्षण हटाने की बात छोड़ दीजिए, भीमराव अंबेडकर का किसी ने सबसे ज्यादा सम्मान किया तो हमने किया है। ओबीसी बिल को पिछले तीन-तीन सत्रों से वे लटकाए रहे। हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। अभी हम सामान्य गरीब वर्ग के लिए आरक्षण लाए। इसमें न पुतले जले, न किसी का हक मारा गया, लेकिन उन्होंने झूठ चलाया- आरक्षण चला जाएगा।

चुनाव आते ही अवॉर्ड वापसी गैंग का काम शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही कोई चुनाव ख़त्म हो जाता है, यह अवॉर्ड वापसी गैंग फिर जाकर सो जाती है। उनके झूठ के उम्र भी ज्यादा नहीं है। कुछ झूठ ऐसे हैं जिन्हें वो खींच-खींचकर लंबा कर रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि चुनाव आते ही अवॉर्ड वापसी गैंग का काम शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही कोई चुनाव ख़त्म हो जाता है, यह अवॉर्ड वापसी गैंग फिर जाकर सो जाती है। उनके झूठ के उम्र भी ज्यादा नहीं है। कुछ झूठ ऐसे हैं जिन्हें वो खींच-खींचकर लंबा कर रहे हैं। आप सच बताते चलें, सच की ताकत इतनी होती है कि झूठ उसके आगे कभी भी नहीं टिक पाएगा। उनकी एक फैक्ट्री है झूठ वाली जो उन्हें बता देती है कि झूठ बोलिए, लेकिन उनकी मेमोरी इतनी कमजोर है कि वो बार-बार आंकड़े बदल देते हैं। ■

भारत ने अंतरिक्ष में मार करने वाली मिसाइल का किया सफल परीक्षण

अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 27 मार्च को ओडिशा स्थित डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक 'मिशन शक्ति' नामक उपग्रह-रोधी (एंटी-सैटेलाइट यानी ए-सैट) मिसाइल परीक्षण किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (बीएमडी) इंटरसेप्टर मिसाइल ने 'हिट टू किल' मोड में पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) में परिक्रमा कर रहे लक्षित भारतीय उपग्रह यानी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक मार गिराया।

यह इंटरसेप्टर मिसाइल दो सॉलिड रॉकेट बुस्टरों से लैस तीन चरणों वाली मिसाइल थी। विभिन्न रेंज सेंसरों से प्राप्त आंकड़ों ने इस बात की पुष्टि की कि यह मिशन अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब रहा।

इस परीक्षण से यह साबित हो गया कि भारत बाह्य अंतरिक्ष में अपनी परिसंपत्तियों (एसेट्स) की रक्षा करने में सक्षम है। इससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि डीआरडीओ के विभिन्न कार्यक्रम अत्यंत कारगर एवं सुदृढ़ हैं।

इस कामयाबी के साथ ही भारत भी अब उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है, जिनके पास इस तरह की अनूठी क्षमता है। अब तक अंतरिक्ष में मार करने की शक्ति केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास थी। यही नहीं, इस परीक्षण ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि स्वदेशी हथियार प्रणालियां अत्यंत सुदृढ़ हैं।

ए-सैट मिसाइल परीक्षण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'मिशन शक्ति' किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल शांति और मानव कल्याण के लिए होगा। उन्होंने इस सफलता के लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा, 'भारत हथियारों की होड़ में कभी नहीं रहा।'

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा, ''यह सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है, निर्णायक नेतृत्व मजबूत देश का निर्माण करता है।'' उन्होंने कहा, ''मैं मिशन शक्ति से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को यह सुनिश्चित करने के लिये धन्यवाद देता हूं कि भारत अपने लोगों के हितों एवं सभी मोर्चों पर सुरक्षा मजबूत कर रहा है।'' श्री शाह ने कहा कि मिशन शक्ति के साथ भारत ने प्रमुख अंतरिक्ष ताकत के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज की है। ■

भारत के पास अंतरिक्ष में सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने की क्षमता: डीआरडीओ

भारत का उपग्रह भेदी मिसाइल परीक्षण महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी विकसित करने में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है और यह कवच के तौर पर काम करेगा। यह बात 27 मार्च को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के अध्यक्ष श्री जी. सतीश रेड्डी ने कही। श्री रेड्डी ने कहा कि परियोजना के लिए मंजूरी करीब दो वर्ष पहले दी गई थी।

अंतरिक्ष में भारत द्वारा उपग्रह को मार गिराए जाने के बाद उन्होंने कहा, ''भारत के लिए यह बड़ी उपलब्धि है।'' इससे देश अंतरिक्ष शक्तियों के चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है। श्री रेड्डी ने कहा कि परीक्षण के लिए उपयोग की गई प्रौद्योगिकी पूरी तरह स्वदेश में विकसित है। उपग्रह को मिसाइल से मार गिराया जाना दर्शाता है कि ''हम ऐसी तकनीक विकसित करने में सक्षम हैं, जो सटीक दक्षता हासिल कर सकता है।''

डीआरडीओ के प्रमुख ने कहा, ''उपग्रह भेदी मिसाइल परीक्षण से हमारी क्षमता का पता चलता है और यह कवच के तौर पर काम करेगा।'' उन्होंने कहा कि परियोजना को काफी तेजी से लागू किया गया और इस तरह के कार्यक्रम लागू करने में यह डीआरडीओ की क्षमता को दर्शाता है।

डीआरडीओ ने कहा कि एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (बीएमडी) इंटरसेप्टर मिसाइल ने सफलतापूर्वक लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) में भारतीय उपग्रह को 'हिट टू किल' मोड में निशाना बना लिया। इसने कहा, ''इंटरसेप्टर मिसाइल तीन चरणों का मिसाइल था जिसमें दो ठोस रॉकेट बूस्टर थे। रेंज सेंसर से निगरानी में पुष्टि हुई कि मिशन ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया।''

श्री रेड्डी ने कहा कि इस परीक्षण से बाहरी अंतरिक्ष में अपने संसाधनों की रक्षा करने की भारत की क्षमता का पता चलता है। साथ ही, विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि परीक्षण किसी देश के खिलाफ नहीं था और बाहरी अंतरिक्ष में भारत किसी हथियार दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता है। ■

भारत में डिजिटलीकरण के चलते धोखाधड़ी के मामलों में कमी आई: आईएमएफ

इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अपनाने से खर्च में 17 प्रतिशत की गिरावट

डिजिटलीकरण के चलते भारत में मनमाने ढंग से काम करने और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 10 अप्रैल को अपनी हालिया रिपोर्ट में यह बात कही। आईएमएफ ने अपनी राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट में कहा कि भारत और इंडोनेशिया में कल्याणकारी योजनाओं के लिए ई-खरीद की शुरुआत से प्रतिस्पर्धा और निर्माण की गुणवत्ता बढ़ी है।

आईएमएफ ने विश्व बैंक के साथ बैठक से पहले जारी अपनी रिपोर्ट में कहा, "भारत में कुछ अहम सुधारों ने डिजिटलीकरण के फायदों को दर्शाया है और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आई है।" उदाहरण के तौर पर भारत में सामाजिक सहायता कार्यक्रम के प्रबंधन में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अपनाने से खर्च में 17 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि इस कार्यक्रम के तहत दिए जाने वाले लाभ में कोई कमी नहीं आई है।

राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक खरीद पर किए गए अध्ययनों से पता लगता है कि प्रक्रियाएं किस प्रकार उत्पादों की कीमतों और गुणवत्ता पर प्रभाव डाल सकती हैं। भारत और इंडोनेशिया में ई-खरीद की शुरुआत होने से प्रतिस्पर्धा और निर्माण की गुणवत्ता बेहतर हुई है।

आईएमएफ ने कहा कि शीर्ष ऑडिट संस्थानों (एसएआई), संसद और नागरिक समाज की जांच से जनता के पैसों के इस्तेमाल में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलती है और अधिकारियों की जवाबदेही बनी रहती है। मुद्राकोष ने कहा कि विशेष जोर के साथ किया गया ऑडिट धन की बर्बादी और कुप्रबंधन की पहचान करके भ्रष्टाचार से लड़ने में मदद कर सकता है। ■

पीएसएलवी-सी45 ने एमीसैट और अन्य देशों के 28 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लांच किया

पीएसएलवी-सी45 ने 1 अप्रैल को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से एमीसैट और अन्य देशों के 28 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लांच किया। पीएसएलवी-सी45 ने दूसरे लांच पैड से भारतीय समयानुसार 9:27 पर उड़ान भरी। वह 17 मिनट और 12 सेकेंड के बाद अपनी कक्षा में स्थापित हो गया।

उसके बाद सौर ऊर्जा से चलने वाली एमीसैट की दो श्रृंखलाएं स्थापित हो गई तथा बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रेकिंग और कमॉन नेटवर्क ने उपग्रह पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। आने वाले दिनों में यह उपग्रह पूरी तरह संचालित हो जाएगा। एमीसैट इसरो के मिनी उपग्रह-2 के आधार पर निर्मित है। इसका भार लगभग 436 किलोग्राम है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पैमाइश के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा चार देशों के भी कुल 28 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों को भी लांच किया गया। इनमें लिथुआनिया के दो, स्पेन का एक, स्विटजरलैंड का एक और अमरीका के 24 उपग्रह शामिल हैं। इस अवसर पर इसरो के अध्यक्ष डॉ. के सिवान ने कहा कि आज का पीएसएलवी अभियान कई मामलों में अनोखा है। उन्होंने वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। ■

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ज़ायेद मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की। इसकी घोषणा यूएई के राष्ट्रपति शेख़ ख़लीफ़ा बिन ज़ायेद अल नहयान ने की।

उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे ऐतिहासिक और व्यापक रणनीतिक संबंध हैं, जो मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका से मजबूत हुए हैं, जिन्होंने इन संबंधों को बड़ा बढ़ावा दिया है। उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए यूएई के राष्ट्रपति उन्हें जायेद मेडल से सम्मानित करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस सम्मान के लिए यूएई का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ट्वीट किया कि वे विनम्रता से इस सम्मान को स्वीकार करते हैं। श्री मोदी ने लिखा, "द्विपक्षीय संबंधों में गर्मजोशी लाने के लिए यूएई के राष्ट्रपति ने उन्हें ज़ायेद मेडल से नवाज़ा है।" ■

एलसीयू एल-56 जहाज नौसेना में शामिल

यार्ड 2097 (एलएसयू एल-56), लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी (एलसीयू) एमके-IV छठी श्रेणी का जहाज है। इस जहाज को मैसर्स जीआरएसई लिमिटेड द्वारा निर्मित कर 30 मार्च को कोलकाता में शामिल किया गया। यह कोलकाता में डीपीएसयू द्वारा तैयार किया गया 100वां जहाज है। जहाज के निर्माण की देखरेख वॉरशिप ओवरसीइंग टीम, कोलकाता द्वारा की गई। जीआरएसई में आयोजित समारोह में शामिल होने वाले गणमान्य लोगों में रक्षा सचिव, वाइस एडमिरल बीके वर्मा एवीएसएम, एडीसी, सी-एनसी अंडमान और निकोबार कमांड तथा वाइस एडमिरल एमएस पवार एवीएसएम, वीएसएम, नौसेना प्रमुख, उप-प्रमुख शामिल थे।

इस लैंडिंग क्राफ्ट से सैनिकों, टैंकों और उपकरणों के परिवहन सहित भारतीय नौसेना की संचालन क्षमता भी बढ़ेगी, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित होगी। जहाज की कमान लेफ्टिनेंट

कमांडर गोपीनाथ नारायण के पास है और इसमें पांच अधिकारियों के अलावा 50 नौसैनिक भी शामिल हैं। ■

मार्च 2019 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक

वित्त वर्ष 2018-19 की सर्वाधिक वसूली

मार्च, 2019 में जीएसटी राजस्व संग्रह कुल मिलाकर 1,06,577 करोड़ रुपये का हुआ, जिसमें 20,353 करोड़ रुपये का सीजीएसटी, 27,520 करोड़ रुपये का एसजीएसटी, 50,418 करोड़ रुपये का आईजीएसटी (आयात पर संग्रहीत 23,521 करोड़ रुपये सहित) और 8,286 करोड़ रुपये का उपकर या सेस (आयात पर संग्रहीत 891 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं। फरवरी माह के लिए 31 मार्च, 2019 तक कुल मिलाकर 75.95 लाख जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल किए गए।

सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी में 17,261 करोड़ रुपये और आईजीएसटी से एसजीएसटी में 13,689 करोड़ रुपये निपटाए हैं। इसके अलावा केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में अनंतिम आधार पर केन्द्र के पास उपलब्ध शेष आईजीएसटी से 20,000 करोड़ रुपये निपटाए। मार्च, 2019 में नियमित निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व कुछ इस तरह से है: सीजीएसटी के लिए 47,614 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 51,209 करोड़ रुपये।

जीएसटी की शुरुआत से लेकर मार्च 2019 के दौरान सर्वाधिक वसूली की गई। मार्च, 2018 में राजस्व 92,167 करोड़ रुपये था और मार्च, 2019 में राजस्व वसूली पिछले वर्ष के समान महीने में संग्रहीत राजस्व की तुलना में 15.6 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2018-19 में अंतिम तिमाही के लिए राजस्व पिछले वर्ष की समान अवधि की वसूली की तुलना में 14.3 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2018-19 के दौरान जीएसटी राजस्व का मासिक औसत 98,114 करोड़ रुपये है, जो 2017-18 की तुलना में 9.2 प्रतिशत अधिक है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अनेक दरों को सुसंगत बनाने के उपायों के बावजूद हाल के महीनों में राजस्व में निरंतर वृद्धि हुई है। ■

एकांगी नहीं, समाज का सर्वांगीण विचार आवश्यक

दीनदयाल उपाध्याय

हम लोग अपने कार्य के अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं। हमारा कार्य अपने समाज का संगठन कर उसे सब प्रकार से वैभवयुक्त बनाए रखना है। इसलिए कई बार जब हम अपने संगठन तथा समाज की संगठित अवस्था का विचार करते हैं तो साथ-साथ प्रश्न उठता है कि उस वैभव की कल्पना का क्या स्वरूप है और क्या आधार हो सकता है, अनेक बार यह प्रश्न उठता है। सन् 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद प्रमुख रूप से अपनी राज्य शक्ति का ध्यान इस समाज जीवन को वैभव युक्त बनाते हुए दिखाई पड़ता है। अनेक योजनाएं संविधान तथा अन्य भी चित्र समाज में भिन्न-भिन्न परिवर्तन करने के लिए क़ानून आदि के द्वारा हुए हैं। जो कुछ ताक़त प्राप्त हुई है, उसके द्वारा समाज जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। सबके सामने यह प्रश्न उठता है। कि इन प्रयासों से हमारा भला होगा कि नहीं। ये प्रयत्न जीवन के अनुकूल बैठेंगे क्या? इस स्वतंत्रता के द्वारा जीवन में कुछ समाधान प्राप्त हो सकेगा या नहीं, इन प्रश्नों पर हमें विचार करना है।

अंग्रेजों के समय ज्यादा कठिनाई नहीं थी। उनको बाहर निकालना ही सर्वसाधारण का लक्ष्य था। कार्य करने में वे बाधा स्वरूप थे। इसलिए उनको दूर कर दिया जाए, ऐसा समझकर ही प्रयत्न चलते थे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसका विचार कुछ अंशों में पहले ही कर लिया था। अंग्रेजों से मुक्ति मिलते ही स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कभी हमने माना नहीं । जहां पर अपना तंत्र होता है, जो जीवन का सब प्रकार से विधान करता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्णय भी करता है। परकीय सत्ता के चले जाने से ही स्वतंत्रता नहीं होती, जीवनतंत्र तो अपना होना चाहिए। स्वतंत्रता के साथ-साथ अपना धर्म, संस्कृति, समाज के संगठन का तथा राष्ट्र की अभिवृद्धि का विचार भी करना होता है। संस्कृति, समाज और धर्म का एक संबंध होता है। उनको छोड़ने पर बचता ही क्या है? इसको हटाकर स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। प्रार्थना में हम नित्य बोलते हैं 'विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्', यह भाव ही राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचा सकेगा, यह एक आवश्यक चीज़ है। उसको छोड़कर नहीं बढ़ सकेंगे।

अंग्रेज़ चले गए तो अब क्या किया जाए, यह समस्या सामने आ गई। आर्थिक दृष्टि के उद्योग-धंधे कैसे चलाए जाएं? इस समस्या को भी सुलझाना था। नज़रें विदेशों की ओर गईं। अमरीका, ब्रिटेन, रूस, जापान और चीन की ओर देखने लगे कि सबने प्रगति कर ली है। कहीं से भी समाचार मिलता है कि उस देश ने प्रगति कर ली है तो वहां पर प्रतिनिधि मंडल भेजे जाते हैं कि वहां जो कुछ चल रहा है, उसको सीखकर यहां के जीवन में प्रकट करो। उत्सुकता तो बहुत है, पर इस प्रकार चारों ओर भेजने से कुछ होगा क्या? लोग कहते हैं कि धर्म-संस्कृति के आधार पर ही बात करने से क्या होगा? बाहर के आधार पर ही प्रगति हो सकती है। ऐसा कहने का एक कारण है। यहां का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, जिसकी शिक्षा-दीक्षा अंग्रेज़ी पद्धति पर हुई है। हम भी अपवाद नहीं हैं। कोई भी आवश्यकता पड़ने पर जो प्राप्त है, उसी ओर निगाह जाती है। प्रत्येक बात के लिए बाहर की ओर देखना स्वाभाविक ही है।

कुछ लोगों की धारणा है कि धर्म और संस्कृति की बात पुराने जमाने की है। जब हमें इस ज़माने की बात करनी है तो सब कुछ आधुनिक ही चाहिए। युगधर्म के नाम से बाहर की अनेक चीजें यहां लाई जाती हैं। युग कोई देश विशेष या समाज विशेष से बंधा हुआ नहीं होता है। इंग्लैंड में जो कुछ चलता है। वही युगधर्म क्यों? उसका तो इससे कोई संबंध नहीं। खाना-पीना है, मेज़-कुरसी पर बैठकर खाना आधुनिक कहलाता है और जमीन पर बैठना पुरानी पद्धति के अंतर्गत आता है। इस बात का संबंध युग से क्यों जोड़ा जाए? पश्चिमीकरण ही आधुनिकता बन गया है। पश्चिम में जो कुछ चल रहा है, वह आधुनिकता के नाम पर हम पर लद रहा है। उनमें भी कुछ पद्धतियां ऐसी हैं, जो हजारों वर्षों से चल रही हैं। जैसे-केक काटना, किसी के स्वास्थ्य के लिए पीना। इनका आधुनिकता के साथ क्या संबंध हो सकता है? विज्ञान की प्रगति का भी और सत्य शोधन का भी आधुनिकता के साथ कोई संबंध नहीं है। आयुर्वेद और एलोपैथी में बिना विचार के एलोपैथी को ही तरतम भाव से स्वीकार किया जाएगा। बुद्धिपूर्वक विचार नहीं होता।

जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसका पूरा विचार नहीं हुआ है। पश्चिम से ही हम क्यों लेते हैं? अपनी संस्कृति को तो आध्यात्मिक मानकर भौतिक समृद्धि के समय विचार में नहीं लाया जाता। एक सज्जन ने कहा कि यदि गुड़ चाहिए तो गुड़ की ही दुकान पर जाना होगा। मिश्री चाहे कितनी ही भली हो। यह कहना गलत है कि हमने भौतिक दृष्टि से विचार ही नहीं किया। पर माना यह गया कि इसमें आत्मा-परमात्मा और मोक्ष परलोक के संबंध में ही विचार हैं। लोगों के कहने के दो

आधार हैं। एक तो यह कि हमारी संस्कृति अच्छी नहीं है और दूसरा यह कि अच्छी है, परंतु बहुत प्राचीन है। महाभारत काल में बड़ी-बड़ी बातें हुई होंगी, पर अब कुछ लेना है तो बाहर वालों से ही लेना होगा। इस संबंध में दो बातों पर विचार करना होगा। मान लो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, परंतु क्या यह उचित है कि हम बाहर से ही लें, जिन्होंने राष्ट्र के टिकने, चलने और समाप्त होने पर साथ-साथ विचार किया, उनका कहना है कि अगर व्यापक रूप से कोई बाहर का अनुकरण करना चाहे तो वह नष्ट हो जाएगा। स्वयं को धोखा देने वाली यह वस्तु है। कुछ जगहों पर तो जैसा कि दक्षिणी अफ्रीका में पता लगा है कि सभ्य बनाने के काल में उनके जीवन की प्रेरणा एकदम समाप्त हो गई है। खाना-पीना, नाचना, पहनना और गिरजाघर में जाना यह सब अंग्रेजों ने अफ्रीकियों को सिखाया। परिणाम यह हुआ है कि उनके जीवन का चैतन्य और उत्साह समाप्त हो गया है। मशीनों की तरह वे लोग काम करते हैं। जनसंख्या भी कम होने लगी है और इस बात का डर है कि तथाकथित सभ्यता का पाठ पढ़ने वाली जातियां भूलोक से समाप्त हो जाएंगी।

थोड़ा-बहुत बाहर से लिया भी जा सकता है। परंतु उनका संबंध स्वयं से सोच लेना चाहिए। भोजन लेते समय शरीर के साथ उसका संबंध देखा जाता है। यदि किसी पदार्थ में एकरूपता होती है, तब उसे काम में लिया जाता है। कोई भी वस्तु खाने पर तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। बाहर का भी अपना बनाकर लेने और उसे पचाने का सामर्थ्य हो तो ही कोई पदार्थ उपयोगी होता है। बिना सामर्थ्य के खाने से हानि होती है। जब बाहर का कुछ लेना होता है तो वह क्या है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और किस रूप में लेना चाहिए-इन दो बातों पर विचार होता है। धातु की भस्म ली जाती है तो इस बात पर विचार किया जाता है कि हमारी प्रकृति कैसी है और खाने के बाद भी कुछ अंशों को बेकार समझकर फेंकना पड़ता है। उसके लिए भी स्थान सोचना पड़ता है। समाज भी बाहर से लेता है और अनेक विकृतियों के रूप में शेषांश को बाहर फेंकता है। बाहर से कुछ लेना है, यानी स्वयं को समाप्त करना है। यदि हमारे पास कुछ नहीं तो अपने अनुकूल यही है कि हम जो भी लें, पराक्रम से लें। आंख बंद करके क्यों लें, यह बात कहने में तो अच्छी है, परंतु विचार करके देखें कि यह तो संपूर्ण शरीर है, त्रिगुणात्मक है। सब अच्छी चीजों को मिलाकर भी जीवन नहीं चलेगा। अच्छे-बुरे को मिलाने से शायद काम चल जाए।

समाज की अपनी जो मनोप्रकृति है। उसी के अनुसार चलना पड़ता है। अपनी प्रकृति बुरी हो तो उसे सुधारना चाहिए। सुधारने के लिए यदि हम बाहर की ओर देखें तो उसमें विकार ही होगा। अतः अपना विचार करें तो अपनी ही परंपरा के आधार पर करें। तर्क में सब कुछ ख़राब होने पर भी बाहर से कुछ नहीं लेंगे। रूढ़ि को ठीक करेंगे और अपनी पद्धति से ठीक करेंगे।

समाज की अपनी जो मनोप्रकृति है। उसी के अनुसार चलना पड़ता है। अपनी प्रकृति बुरी हो तो उसे सुधारना चाहिए। सुधारने के लिए यदि हम बाहर की ओर देखें तो उसमें विकार ही होगा। अतः अपना विचार करें तो अपनी ही परंपरा के आधार पर करें। तर्क में सब कुछ ख़राब होने पर भी बाहर से कुछ नहीं लेंगे। रूढ़ि को ठीक करेंगे और अपनी पद्धति से ठीक करेंगे। समाज सुधार के प्रयत्न अपने यहां बराबर हुए हैं। इसी युग में महर्षि दयानंद ने समाज को बदला है। उन्होंने इंग्लैंड की तरफ़ देखने को नहीं कहा। जीवित समाज में ऐसे प्रयास होते हैं।

यह समाज शुद्ध समाज है, ऐसा नहीं कहा जा सकेगा। जैसे कमरे की सफ़ाई रोज़ करनी पड़ती है और एक दिन में सारी नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार समाज को भी । शुद्ध करना पड़ता है। लोटा भी दूसरे दिन साफ़ चाहिए। गणवेष के बूट और बैल्ट को रोज़ पॉलिश करना पड़ता है। ख़राबियों को ठीक करने वाली चीज़ समाज में चलती रहती है। दूसरों के आधार पर प्रयत्न करना लाभ नहीं देगा। मूल तंतुओं को तोड़कर नया प्रयास करने में जीवन समाप्त हो जाएगा।

जब हम अपनी चीजों का विचार करते हैं तो पता लगता है कि अपनी पद्धति तो अन्यों से चार क़दम आगे है। एकांगी विचार नहीं तो समाज का सर्वांगीण विचार हमने किया है। इसमें कोई ख़राबी है तो वह भी हमारी है। अतः अच्छी है। वही हमारी प्रकृति को लगती है। बाहर की ओर देखना मूर्खता है। घर के रत्न को छोड़कर बाहर की कौड़ियों की ओर देखना तो और भी मूर्खता है और सब इन्हीं कौड़ियों के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजे जाते हैं तो कितनी बड़ी मूर्खता सिद्ध होती है। जब हमने धर्म और संस्कृति का विचार किया है तो उसके आधारों पर विचार तो पहले किया है।

मनुष्य पैदा हुआ, उसकी क्रिया के पीछे प्रेरणा क्या है? जो भी पैदा होता है, उसे जिंदा रहने की इच्छा होती है। इसको प्राणेषणा कहते हैं। इसी प्रेरणा से सारी बातों का निर्माण होता है। जीवित रहने के लिए यह लाख दौड़-धूप करता है। जो चीज़ उसको जीवित रखने में सहायक होती है, उसे वह सुख मानता है। जो सहायक नहीं होती, उसे दुःख। इसी सुख की इच्छा करने को सुखेषणा कहते हैं। उसके सारे प्रयत्न इसी कारण कामना से होते हैं। इसी सुख को प्राप्त करना और कितनी मात्रा में तथा कितनी अच्छी तरह लेने का वह प्रयास करता है। ■ (शेष अगले अंक में)...

संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग: नई दिल्ली
(-पाञ्चजन्य, जनवरी १५, १९६०)

महात्मा ज्योतिबा फुले

(11 अप्रैल 1827 – 28 नवंबर 1890)

महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती चिमणाबाई तथा पिता का नाम श्री गोविन्दराव था। ज्योतिबा बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने मराठी में अध्ययन किया। वे महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक एवं दार्शनिक थे।

महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार आंदोलन जोरों पर था। जाति-प्रथा का विरोध करने और एकेश्वरवाद को अमल में लाने के लिए 'प्रार्थना समाज' की स्थापना की गई थी, जिसके प्रमुख गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर थे।

उस समय महाराष्ट्र में जाति-प्रथा वीभत्स रूप में फैली हुई थी। स्त्रियों की शिक्षा को लेकर लोग उदासीन थे, ऐसे में ज्योतिबा फुले ने समाज को इन कुरीतियों से मुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए। उन्होंने महाराष्ट्र में महिला शिक्षा तथा अछूतोद्धार का काम आरंभ किया। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए विद्यालय खोला।

इन प्रमुख सुधार आंदोलनों के अतिरिक्त हर क्षेत्र में छोटे-छोटे आंदोलन जारी थे, जिसने सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर लोगों को परतंत्रता से मुक्त किया। लोगों में नए विचार, नए चिंतन की शुरुआत हुई, जो आजादी की लड़ाई में उनके संबल बने।

ज्योतिबा यह जानते थे कि देश व समाज की वास्तविक उन्नति तब तक नहीं हो सकती, जब तक देश का हर व्यक्ति जाति-पांति के बन्धनों से मुक्त नहीं हो पाता। उन्होंने नवयुवकों का आह्वान किया कि वे देश, समाज, संस्कृति को सामाजिक बुराइयों तथा अशिक्षा से मुक्त करें और एक स्वस्थ, सुन्दर सुदृढ़ समाज का निर्माण करें। मनुष्य के लिए समाज सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इससे अच्छी ईश्वर सेवा कोई नहीं। मानव-मानव के बीच का भेद उन्हें असहनीय लगता था।

दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने 'सत्यशोधक समाज' स्थापित किया। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 ई. में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें 'महात्मा' की उपाधि दी। वे बाल-विवाह विरोधी और विधवा-विवाह के समर्थक थे। ज्योतिबा फुले की मृत्यु 28 नवंबर 1890 को पुणे में हुई। ■

सुन्दर सिंह भण्डारी

(12 अप्रैल 1921– 22 जून 2005)

सुन्दर सिंह भण्डारी का जन्म 12 अप्रैल 1921 को उदयपुर के एक जैन परिवार (राजस्थान) में हुआ। श्री भण्डारी के पिता डा. सुजान सिंह भण्डारी डाक्टरी पेशे से संबद्ध थे। उनकी शिक्षा कई स्थानों पर हुई। उन्होंने उदयपुर से सिरोही से इंटरमीडिएट परीक्षा पास की और डीएवी कॉलेज, कानपुर से बीए और एम.ए. किया। उन्होंने अर्थशास्त्र में एम.ए. किया और बाद में लॉ का अध्ययन किया।

श्री भण्डारी 'सरल जीवन और उच्च विचारों' के प्रतीक थे। शांत भाव के भण्डारी जीवन भर अविवाहित रहे और राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। 1942 में शिक्षा पूरी करने के बाद मेवाड़ उच्च न्यायालय में लीगल प्रेक्टिस शुरू की। 1937 में उन्होंने एस.डी. कॉलेज, कानपुर में प्रवेश लिया, जहां पं. दीनदयाल उपाध्याय उनके सहपाठी थे। 1937 (दिसम्बर) में इंदौर के बालू महाशब्दे ने उन्हें कानपुर के निकट नवाबगंज की आर.एस.एस शाखा में ले गए थे। तब से वे सदैव अपनी अंतिम सांस तक आरएसएस की विचारधारा के प्रति वचनबद्ध रहे।

1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। रा.स्व.संघ से जिन प्रमुख कार्यकर्ताओं को जनसंघ में कार्य के लिए भेजा गया था, उनमें उनका नाम प्रमुख रूप से शामिल था। 1951 से 1965 तक श्री भण्डारी ने राजस्थान जनसंघ में महामंत्री का दायित्व निभाया। इसके अलावा वे 1963 में जनसंघ के अखिल भारतीय मंत्री थे। पं. दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद 1968 में श्री भण्डारी को अखिल भारतीय महामंत्री (संगठन) बनाया गया। भण्डारी जी ने कार्यकर्ताओं के सामने सरलता, सहनशीलता और मितव्ययता का उदाहरण पेश किया।

उन्होंने 1977 तक जनसंघ महामंत्री के पद पर कार्य किया। वह 1966–1972 के समय राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए, जब वह उस समय 'मीसा) के अन्तर्गत हिरासत में थे। 1998 में उनका राज्य सभा का कार्यकाल समाप्त हुआ, तब उन्हें बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1999 में उन्हें गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया गया। 22 जून 2005 को उनका स्वर्गवास हो गया। ■

कांग्रेस का घोषणापत्र 2019

संस्थानों को नष्ट करने और आतंकवादियों की मदद करने की स्वतंत्रता

अरुण जेटली

स्वर्गीय रामनाथ गोयनका शायद देश के मीडिया मालिकों के बीच सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सेंसरशिप के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने अखबार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। आपातकाल के दौरान उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया और लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ाई में सबसे आगे रहे। स्वतंत्र मीडिया के लिए उनकी दलीले एक श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसका सभी मीडिया घरानों को अनुसरण करना चाहिए।

रामनाथ गोयनका संविधान सभा के सदस्य भी थे। मौलिक अधिकारों पर बहस के दौरान उन्होंने एक शानदार भाषण दिया था और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का मुद्दा और उसके बाद प्रतिबंध की बात सामने आई, तो उन्होंने हस्तक्षेप किया। उन्होंने एक ऐसे समय की परिकल्पना की थी, जहां मुक्त मीडिया अधिकार पूर्वक मालिकों की जेब पर अंकुश लगा सके। उनका मानना था कि आर्थिक रूप से कमजोर मीडिया हमेशा कमजोर रहेगा।

स्वतंत्र मीडिया के लिए इंदिराजी की नफरत सर्वविदित थी। वह भारत के प्रमुख समाचार पत्रों को 'एकाधिकार प्रेस' या 'जूट प्रेस' कहकर संबोधित करती थी। 1960 और 1970 में कांग्रेस ने प्रयोगात्मक तौर पर बहुत से दुस्साहस किए। वे समाचार पत्रों की लागत को पृष्ठों की संख्या से जोड़ना चाहते थे, समाचार पत्र के आकार को प्रतिबंधित करते थे और साथ ही प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों की संख्या को भी सीमित करते थे। इन प्रतिबंधों को चुनौती दी गई थी और सकाल, इंडियन एक्सप्रेस और अंततः 1974 में बेनेट कोलमैन मामले में कोर्ट ने समाचार पत्रों के हक में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। अदालत ने इस तर्क को सही ठहराया कि अन्य मौलिक अधिकारों के विपरीत, जिन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक ऐसा विशेषाधिकार था, जिस पर केवल अनुच्छेद 19 (2) में उल्लिखित प्रतिबंधों के संदर्भ में ही कोई कार्रवाई हो सकती थी। इस तरह के प्रतिबंधात्मक उपाय, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, अनुमेय नहीं थे क्योंकि वे अनुच्छेद 19 (2) के दायरे में नहीं आते थे।

स्वतंत्र मीडिया के लिए इंदिराजी की नफरत सर्वविदित थी। वह भारत के प्रमुख समाचार पत्रों को 'एकाधिकार प्रेस' या 'जूट प्रेस' कहकर संबोधित करती थी। 1960 और 1970 में कांग्रेस ने प्रयोगात्मक तौर पर बहुत से दुस्साहस किए। वे समाचार पत्रों की लागत को पृष्ठों की संख्या से जोड़ना चाहते थे, समाचार पत्र के आकार को प्रतिबंधित करते थे और साथ ही प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों की संख्या को भी सीमित करते थे।

दूसरी महत्वपूर्ण मानसिकता जिसके साथ नेहरू-इंदिरा युग को जोड़ा जा सकता था, 'बड़ा बुरा है' और 'छोटा बेहतर है'। इसने एमआरटीपी और आईडीआरए के तहत लाइसेंसिंग आवश्यकताओं जैसे प्रतिबंधात्मक विधानों को जन्म दिया। उदारीकरण के साथ वाजपेयी सरकार ने इसको ध्वस्त कर दिया और नरसिम्हा राव सरकार ने इसमें काफी बदलाव किए।

मीडिया और कांग्रेस का घोषणापत्र

यह ध्यान में रखना होगा कि इंदिराजी ने आपातकाल के दौरान प्रेस परिषद अधिनियम को रद्द कर दिया था और अध्यादेश द्वारा प्रेस परिषद को समाप्त कर दिया था। आज कांग्रेस इसे मजबूत करना चाहती है और मीडिया को राष्ट्रीय हितों से संबंधित घटनाओं की कवरेज पर एक आचार संहिता बनाने की अनुमति देती है। जबकि पहले से मौजूद दिशानिर्देशों के बाद यह मुद्दा बेमानी है। प्रारंभ में उन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कुछ मामले सामने आए थे, जहां मीडिया संगठनों को एक सलाह या चेतावनी दी गई थी। हाल में अधिकांश अवसरों पर मीडिया संगठनों ने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए ही काम किया है। यदि समस्या गंभीर नहीं है, तो मीडिया को क्यों विनियमित करें?

यह उल्लेख किया जाना जरुरी है कि घोषणापत्र का मसौदा तैयार करने वाले सज्जन वही हैं, जिन्होंने साल 1988 में एक नाकामयाब मानहानि विधेयक का मसौदा तैयार किया था। यह विधेयक मानहानि के लिए

बढ़ी हुई सजा की वकालत करता था, जिसमें पहले अपराध के लिए दो साल की सजा और उसके बाद के अपराधों के लिए पांच साल तक की सजा की बात थी। आज विपक्ष में रहते हुए, वह मानहानि को गैर आपराधिक अपराध बनाना चाहते हैं।

अधिक खतरनाक प्रावधान घोषणापत्र के पैराग्राफ 33 (4) और 33 (5) में निहित है। पहला, एकाधिकार को रोकने के लिए कानून का वादा करता है और दूसरा मीडिया के अलग-अलग क्षेत्रों की मीडिया होल्डिंग्स पर रोक लगाने की बात करता है। इसके अतिरिक्त अन्य व्यवसाय करने वाले समूह द्वारा मीडिया के स्वामित्व को प्रतिबंधित करने की मांग की जाती है। इन मामलों को भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के पास भेजा जाएगा। रामनाथ गोयनका की भविष्यवाणी सच हो रही है। यह दोनों बातें मीडिया विरोधी और कांग्रेस की 'बड़ा बुरा है' पारंपरिक विचारधारा को परिभाषित करता है। यह वाम और तानाशाही दोनों दृष्टिकोणों का एक खतरनाक गठजोड़ है।

यह घोषणापत्र आतंकवादियों, अपराधियों और विद्रोहियों के प्रति उदार दिखता है, लेकिन यह भारत में स्वतंत्र मीडिया की वर्तमान संरचना को ध्वस्त करने की ओर इशारा करता है। भारत को प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो और अब डिजिटल मीडिया की बहुलता है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं यह विचार रखता हूं कि यदि कुछ मीडिया संगठन मेरी पार्टी के दृष्टिकोण के विरोध में हैं, तो वे उपलब्ध मीडिया समाचारों के महासागर का एक मामूली हिस्सा भर हो सकते हैं। यह हर दूसरे पक्ष पर लागू होता है। अंततः भारतीय मीडिया के आकार की विशालता चीजों को संतुलित करती है। फिर संसदीय कानून की आवश्यकता क्यों है? इस तरह के संसदीय कानून की सलाह दी जाती है क्योंकि:

1. संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में कोई प्रतिबंध अब लागू किए जाने वाले प्रतिबंधों के लिए किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। जिस तरह 1960 और 1970 के दशक के कानून को हटाया गया था, वैसे ही किसी भी कानून को संवैधानिक चुनौती दी जा सकती है।

2. क्रॉस मीडिया होल्डिंग्स की अवधारणा संयुक्त राज्य में प्रासंगिक थी जहां एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर एक शहर में उपलब्ध समाचार पत्रों की संख्या एक या दो थी। चैनलों की बहुलता भी नहीं थी। उपग्रह चैनलों के अस्तित्व में आने के साथ ही भारत में नागरिकों के पास सैकड़ों चैनलों, कई समाचार पत्रों और डिजिटल माध्यमों का विकल्प सुनिश्चित हुआ है। क्रॉस होल्डिंग अवधारणा भारत में एक अप्रचलित विचार है। एकाधिकार का 'वास्तविक और निकटस्थ' कोई खतरा नहीं है।

3. प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, क्रॉस मीडिया होल्डिंग्स की अवधारणा ध्वस्त हो गई है। एडीटीवी एक चैनल चलाता है और इसकी एक शक्तिशाली वेबसाइट है जो एक समाचार पत्र के उद्देश्य को पूरा करती है। देश भर के कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अख़बार, न्यूज़ चैनल, डिजिटल वेबसाइट और समाचार पत्र भी चलाते हैं। तो इस बात से जनहित कैसे प्रभावित होता है यदि आप एक माध्यम को चलाते हैं, तो आपको दूसरे को चलाने से रोक दिया जाना चाहिए? क्या एकाधिकार का खतरा सच में उत्पन्न हो रहा है? मेरे जैसे नागरिक भी फेसबुक और ट्विटर पर ब्लॉग लिखते हैं और अपनी बात को ऑडियो/वीडियो रूप में भी जारी करते हैं। प्रौद्योगिकी ने हमें सक्षम बनाया है। क्रॉस होल्डिंग की पूरी अवधारणा है कि यदि आप मीडिया के एक खंड के मालिक हैं, तो आपको दूसरे का मालिक बनने का अधिकार नहीं यह तर्क मौजूदा तकनीकी विकास के कारण अप्रचलित लगता है।

इतिहास गवाह है कि फर्जी समाचार और पेड न्यूज के मामले में, साथ ही राजनीतिक और सरकारी दबावों को बड़े संगठन ने पेशेवर तरीके से संभाला हैं। उनके पास प्रतिरोध करने की क्षमता होती है। कांग्रेस क्यों इस बात को हवा देना चाहती है? कांग्रेस के इस कदम का भी वही हश्र होगा जो मानहानि विधेयक,1988 का हुआ था।

मीडिया अध्याय में खतरनाक विचार

यह खतरनाक अध्याय घोषणापत्र के पैरा 33 (5) में निहित है। जो इंटरनेट की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक कानून का वादा करता है और इसे निरंकुश ढंग से चलाने की बात करता है।

इस प्रावधान का आमतौर पर केवल तभी प्रयोग किया जाता है जब आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ अभियान चल रहा हो। उन्हें तुरंत कदम उठाना होता है। उग्रवाद विरोधी अभियानों के दौरान या जहां जाति या सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, वहां इस तरह के प्रतिबंध राष्ट्रीय हित में लगाए जाते है। हिंसा या बड़े पैमाने पर सामाजिक तनाव की कुछ स्थितियों में सोशल मीडिया पर उन्माद पैदा किया जा सकता है। इससे शरारती तत्व अपने उद्देश्य में कामयाब होते है। कांग्रेस चाहती है कि इस संबंध में सुरक्षा बलों की शक्तियों को सीमित किया जाए।

इस घोषणा पत्र में मीडिया अध्याय में ऐसे हर एक सुझाव शामिल हैं, जो मुक्त पत्रकारिता और भारतीय मीडिया की बहुलता को विनियमित और प्रतिबंधित करेंगे। यह एक पुराना दांव है। यह समय के अनुरूप नहीं है। हालांकि, इस अध्याय को बनाते समय भी आतंकवादियों और विद्रोहियों का विशेष ध्यान रखा गया है। ■

(लेखक केंद्रीय मंत्री है)

कांग्रेस का घोषणापत्र आतंकवादियों, अपराधियों और विद्रोहियों के प्रति उदार दिखता है, लेकिन यह भारत में स्वतंत्र मीडिया की वर्तमान संरचना को ध्वस्त करने की ओर इशारा करता है। भारत को प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो और अब डिजिटल मीडिया की बहुलता है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, मैं यह विचार रखता हूं कि यदि कुछ मीडिया संगठन मेरी पार्टी के दृष्टिकोण के विरोध में हैं, तो वे उपलब्ध मीडिया समाचारों के महासागर का एक मामूली हिस्सा भर हो सकते हैं।

'पाकिस्तान को सीधा करने वाला एक ही नाम है नरेंद्र मोदी'

सोनगढ़ (गुजरात)

लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10 अप्रैल को गुजरात पहुंचे। जूनागढ़ में एक आम सभा को संबोधित करने के बाद सोनगढ़ में भी एक आम सभा को संबोधित किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र भी सरदार के विचारों के विपरीत है। सरदार पटेल का रास्ता कांग्रेस ने छोड़ दिया है। आज यदि पाकिस्तान को सीधा कर सकता है, तो वह है नरेंद्र मोदी।

श्री मोदी ने कहा कि कश्मीर का मामला जवाहर लाल नेहरू के कारण सुलझ नहीं पाया है। आज कांग्रेस ने सरदार पटेल का रास्ता छोड़ दिया है। कांग्रेस ने जो खेल सरदार पटेल और मोरारजी देसाई के साथ खेला था, आज मेरे साथ खेल रही है। सोनगढ़ के गुणसदा में कांग्रेस पर तीखे प्रहार करते हुए श्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस ने यदि सरदार पटेल का रास्ता पकड़ा होता, तो देश आज कहां पहुंच गया होता। जो बात सरदार को पसंद नहीं थी, वही आज कांग्रेस कर रही है। कश्मीर का मामला सरदार से लेकर नेहरू ने क्या किया, यह सब जानते हैं। आज आतंकवाद भी उन्हीं के कारण इतना चल पाया है।

कांग्रेस के घोषणा पत्र का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस कश्मीर से सुरक्षाबलों को हटाने का वचन देती है। इस तरह से वह देशद्रोहियों को खुले आम घूमने की इजाजत देती है। देश के टुकड़े करने का पाप कांग्रेस करेगी, ऐसा वचन वह दे रही है। उसे फिर से सत्ता पर काबिज होना है। इसलिए पाकिस्तान जो करना चाहता है, वह छूट कांग्रेस देना चाहती है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात तो दूर, परंतु देश के और टुकड़े हों, कांग्रेस यही चाहती है।

श्री मोदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाद में मोरारजी देसाई को हैरान करने वाली कांग्रेस मुझ पर प्रहार कर रही है। कांग्रेस को ऐसा लगा था कि हमारी सरकार एक साल भी पूरा नहीं कर पाएगी और हमने पांच साल पूरे कर लिए। मुझे आप लोगों ने तराशा है, 23 मई के बाद हम फिर सत्ता पर काबिज होंगे। आप इन लोगों को सफल मत होने देना। देश के लिए बलिदान देने वालों के लिए यदि आपके दिल में दर्द है, तो इन्हें कभी वोट मत देना।

श्री मोदी ने कहा कि इस राजे-महाराजे (कांग्रेस) को चाय वाला सहन नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे खिलाफ रोज-रोज अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है। किंतु हम काम करने वाले हैं। चौकीदार को चोर कहने वालों के घर से रुपए निकल रहे हैं। मोदी को निपटा दो, कहने वाले एक हो गए हैं। देश को लूटने वाले एक हो गए हैं। इनका मुद्दा तो एक ही है मोदी को हटाओ, पर मेरा मुद्दा है देश हित।

श्री मोदी ने कहा कि देश के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और ये लोग हमसे उसका सबूत मांग रहे हैं। पाकिस्तान आज देश-दुनिया के सामने रो रहा है, उसकी आवाज ये लोग नहीं सुन रहे हैं। पाकिस्तान को सीधा करने वाला केवल एक ही है, वह है नरेंद्र मोदी। आज हम आतंकवाद के हालात बदल रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तो यहां से भ्रष्टाचार खत्म किया। अब दिल्ली में हूं, वहां से पूरे देश में भ्रष्टाचार खत्म किया है।

कूचविहार (पश्चिम बंगाल)

'मोदी-मोदी के नारों से दीदी की उड़ी नींद'

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 अप्रैल को कूचविहार की रैली में पश्चिम बंगाल की सीएम व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी-मोदी के नारों से दीदी की नींद उड़ गई है।

श्री मोदी ने बंगाल की महान विभूतियों को नमन करते हुए सभा शुरू की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनता का उत्साह देख मैं अभिभूत हूं। जो जहां है, वहीं बैठ जाए। भीड़ बहुत है। मैं फिर आऊंगा और आपके दर्शन करूंगा। आप जितना मोदी-मोदी करते हो, उतनी ही दीदी की नींद उड़ जाती है। वही, दीदी जो बौखला गई है, जो स्पीडब्रेकर है। बंगाल ने अब यह ठान लिया है कि अब परिवर्तन कर देना है। क्योंकि अब नामुमकिन भी मुमकिन है।

श्री मोदी ने कहा कि गरीबों की रसोई में गैस पर खाना पकेगा।

टेलीफोन पर बात करना मुफ्त हो जाएगा। इंटरनेट फ्री हो जाएगा। बांग्लादेश से जमीन समझौता भी नामुमकिन था। भारत आतंकियों के घर मे घुस कर मारेगा। यह भी नामुमिन था, लेकिन अब यह मुमकिन है।

उन्होंने कहा कि आए दिन आतंकी हमले होते थे, यह पहले की सरकार को पता था, लेकिन चौकीदार को जब से आपने बिठाया है। तब से कोई डरा नहीं सका। उनके मुताबिक, दीदी परेशान है। दिन रात बस मोदी मोदी हटाओ का नारा। आप का प्यार, देश का प्यार, मेरे साथ है। मुझे कोई हटा पाएगा क्या।

श्री मोदी ने कहा कि घुसपैठियों को बिठाकर दीदी मानुष के साथ अन्याय कर रही है।

उदयपुर (त्रिपुरा)

'मिडिल क्लास पर ज्यादा टैक्स लगाकर 'बदला' लेना चाहती है कांग्रेस'

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 अप्रैल को अपनी दूसरी रैली त्रिपुरा में की। इस रैली में श्री मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि वह मध्यम वर्ग पर ज्यादा टैक्स लगाकर उसे बर्बाद करना चाहती है।

उदयपुर में हुई इस जनसभा में श्री मोदी ने कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मिलकर मध्यम वर्ग को सजा देने का मन बना चुके हैं, जिनसे लोगों को बचकर रहना चाहिए। श्री मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट दल त्रिपुरा और केरल में कुश्ती करते हैं और दिल्ली में उन्हें (मोदी को) गाली देने के लिए एक हो जाते हैं।

रैली में कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने उसे 'ढकोसला पत्र' बताया। श्री मोदी ने कहा कि 50-60 पेज के उस घोषणा पत्र में एक बार भी मध्यम वर्ग का जिक्र नहीं है। श्री मोदी बोले कि मध्यम वर्ग ने मिलकर भाजपा की सरकार बनवाई थी, इसलिए अब कांग्रेस और बाकी दल मिलकर मिडिल क्लास को 'सजा' देना चाहते हैं। श्री मोदी ने इशारों-इशारों में कहा कि कांग्रेस सरकार जो न्याय योजना लाने वाली है उसके लिए पैसा मिडिल क्लास पर ज्यादा टैक्स लगाकर निकाला जाएगा।

श्री मोदी ने कहा, 'कांग्रेस समेत कुछ दल मध्यम वर्ग पर अधिक टैक्स लगाने की कोशिश में है। मैं पूछता हूं कि क्या ऐसा करके लाइसेंस राज फिर से लाया जाएगा। इससे मिडिल क्लास बर्बाद हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि मध्यम वर्ग को खत्म कर दोगे तो देश का भला कैसे होगा।'

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए श्री मोदी ने आगे कहा कि चौकीदार को हराने के लिए नामदार (राहुल गांधी) भारत के टुकड़े करने की इच्छा रखने वालों का भी साथ दे रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट पर्दे के पीछे मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं लेफ्ट पर हमला बोलते हुए श्री मोदी ने कहा कि लेफ्ट पार्टी के लिए अपना संविधान देश के संविधान से भी ऊपर है। श्री मोदी बोले, 'पहले जिनके दर्जनों सांसद होते थे, वे आज हांफ रहे हैं। पहले इनके नेता जमीन पर राजनीति करते थे और अब सिर्फ टीवी स्टूडियो में नजर आते हैं।'

इम्फाल (मणिपुर)

'कांग्रेस भारत से ज्यादा पाकिस्तान का गुणगान कर रही है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अप्रैल को कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के जरिये भारत से ज्यादा पाकिस्तान का गुणगान कर रही है। श्री मोदी ने इम्फाल स्थित हाप्ता कांगजेईबुंग मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दावा किया था कि कोई भी संविधान के अनुच्छेद 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं

कर सकता, इस अभिकथन से पाकिस्तान सहमति रखता है। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस दुनियाभर में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के प्रसार में मदद कर रही है...कांग्रेस का पाखंडी दस्तावेज (घोषणा पत्र) भारत से ज्यादा पाकिस्तान का गुणगान करता दिखता है।" उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है और राज्य से संबंधित नये कानून बनाने की संसद की शक्तियों को सीमित करता है।

श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी है जो भारत और जम्मू-कश्मीर के लिये अलग अलग प्रधानमंत्री चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर में कई वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस मणिपुर सहित पूर्वोत्तर में कोई भी विकास लाने में असफल रही। श्री मोदी ने कहा, 'भाजपा पूर्वोत्तर में कांग्रेस द्वारा किये गए नुकसान को सही करने की दिशा में काम कर रही है..क्षेत्र अंततः मुख्यधारा में आ रहा है।" ■

नवीन सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान

गजपति (ओडिशा)

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस एवं बीजू जनता दल (बीजद) को आप लोगों ने लंबे समय तक शासन करने का अवसर दिया। इस बार भाजपा को अवसर दें, पांच साल में ओडिशा को देश का एक नंबर राज्य बना कर दिखा देंगे। इसके लिए आपको नवीन पटनायक सरकार को उखाड़ कर फेंक देने का संकल्प लेना होगा।

यह बात 1 अप्रैल को श्री शाह ने गजपति जिला अंतर्गत पारलाखेमुंडी में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही।

श्री अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत से ही नवीन पटनायक सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि नवीन बाबू ओडिशा में 19 साल से शासन कर रहे हैं, मगर आज तक ओडिया भाषा में बात करना तक नहीं सीखे। हाल ही में उन्होंने सूरत में एक सभा की थी, जिसमें 30000 ओडिया लोग शामिल हुए थे। यहां सवाल ये उठता है कि आखिरकार राज्य के लोग अपने घर को छोड़कर काम-धंधा के लिए दूसरे राज्यों में क्यों जाना पड़ रहा है। 19 साल से नवीन बाबू की सरकार क्या कर रही है, भाजपा की सरकार ओडिशा में बनने के बाद यहां के लोगों को सूरत नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें अपने गांव में ही अपने घर पर रोजगार मिलेगा।

श्री शाह ने यह भी कहा कि राज्य की सरकार पश्चिम ओडिशा एवं मध्य ओडिशा के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। यह सरकार किसी भी कार्य के लिए कमीशन लेती है। इस सरकार ने महाप्रभु के रत्न भंडार को नहीं छोड़ा। नवीन सरकार ने महेंद्र तनया प्रोजेक्ट को नहीं होने दिया। हर घर में अभी तक इस सरकार ने पानी तक मुहैया नहीं कर पाई है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। नवीन बाबू ने भ्रष्टाचार के सिवा और कुछ नहीं किया है। गरीबी को कैसे दूर किया जाएगा, इसके लिए नवीन बाबू को ट्यूशन लेनी चाहिए। ट्यूशन के लिए नवीन बाबू को फीस देनी होगी। हम उन्हें मुफ्त में ट्यूशन देंगे, मगर इसके लिए अभी समय नहीं है, यह समय चला गया। ओडिशा को एक युवा एवं नए मुख्यमंत्री की जरूरत है।

उन्होंने इस अवसर पर केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार लाने के लिए लोगों से आह्वान किया। श्री शाह ने कहा कि हम जहां भी जा रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं मोदी सरकार आनी चाहिए। पूरे देश में लोग एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। देश में एक बार फिर मोदी सरकार लाने के लिए आप संकल्प लें। श्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है, जो 24 घंटा में 18 घंटा गरीब लोगों के विकास के लिए चिंतन कर रहा है

देश उनके हाथों में सुरक्षित है।

इसके साथ ही श्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी हमला बोला। समझौता एक्सप्रेस मामले में सभी हिंदू निर्दोष साबित हुए हैं। ऐसे में हिंदू कभी आतंकी नहीं होते हैं। हिंदू देश का निर्माण करते हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद कांग्रेस का बयान निंदनीय है। मोदी मौनी बाबा नहीं है। आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा गया।

राजौरी (जम्मू-कश्मीर)

'जम्मू-कश्मीर समस्या के लिए नेहरू हैं जिम्मेदार'

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 3 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के सुंदरबनी में रोहिंग्याओं को देश में घुसने से रोकने के लिए भाजपा नीत राजग सरकार को श्रेय देते हुए कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की समाप्ति से पहले सभी घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल देंगे।

श्री शाह ने अवैध प्रवासियों को देश के लिए "दीमक" बताया। उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है। राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के करीब स्थित इस सीमावर्ती शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुये श्री शाह ने पूछा ''भाजपा सरकार द्वारा किया गया सबसे बड़ा काम देश में रोहिंग्याओं की घुसपैठ को खत्म करना था। पीडीपी ने रोहिंग्याओं (राज्य में) का स्वागत किया। मुझे बताइए कि क्या रोहिंग्याओं की घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं," बड़ी संख्या

में मौजूद श्रोताओं ने जोरदार आवाज में ''हां''के साथ जवाब दिया।

श्री अमित शाह ने इससे पूर्व अपने भाषण में राहुल गांधी के अमेठी के अलावा केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ने के फैसले पर निशाना साधा था। चुनाव प्रचार के क्रम में यूपी में एक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने राहुल गांधी की दो सीटों से चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि अमेठी में हिसाब-किताब चुकता होने वाला है, इसलिए राहुल गांधी केरल भाग रहे हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि अमेठी में हार की डर की वजह से राहुल गांधी वायनाड भाग रहे हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की वोटबैंक की राजनीति ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। इसी का नतीजा है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर केरल की ओर भागे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार अमेठी में उनका हिसाब-किताब होना तय है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिन्दू समुदाय पर आतंकवाद का टैग लगाया, लेकिन सत्य को आप छुपा नहीं सकते। सूर्य को कितने भी बादलों में छिपा दो लेकिन सत्य और सूर्य तेजस्वी होकर हमेशा चमकते हैं। आज इस जजमेंट ने साबित कर दिया हैं कि स्वामी असीमानंद और बाकी सभी लोग निर्दोष है।

चांगलांग (अरुणाचल प्रदेश)

'केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में शांति लाने का काम किया'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 5 अप्रैल को कहा कि पांच साल पहले पूर्वोत्तर भारत डिस्टर्ब था और बहुत कम विकास हुआ था, लेकिन मात्र 5 साल में बीजेपी की सरकार में यहां शांति कायम हुई है और विकास की राह पर पूर्वोत्तर चल पड़ा है।

श्री अमित शाह ने कहा- मोरारजी देसाई अंतिम पीएम थे, जिन्होंने पूर्वोत्तर में एनईसी की बैठक में भाग लिया था। 40 साल बाद पीएम मोदी के रूप में कोई प्रधानमंत्री शिलांग में हुई बैठक में शामिल हुआ। श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि मोदी जी ने अपने मंत्रियों को हर पखवाड़े उत्तर-पूर्व की यात्रा करने का निर्देश दिया था। ऐसा मुद्दों पर ध्यान देने और उन्हें हल करने के लिए किया गया था। पूर्वोत्तर के सभी हिस्से अब वायुमार्ग और रेलवे से जुड़े हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश की सड़कों के विकास के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपये दिए हैं।

श्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी पार्टी को आड़े हाथों लिया। श्री शाह ने कहा कि एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में खुशी थी, लेकिन पाकिस्तान और राहुल गांधी के चेहरे पर मातम था। उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा कहते हैं कि एयरस्ट्राइक क्यों की, इनसे बात करनी चाहिए थी। लेकिन हमारी सरकार आतंकियों से कभी बात नहीं करेगी।'

श्री अमित शाह ने आगे कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादी पहले भी देश में हमला किया करते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारें कुछ नहीं करती थीं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान को मुहंतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो देश में करारा जवाब देने की मांग उठ रही थी। पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को एयर स्ट्राइक करने का आदेश दिया और पाकिस्तान ने जो बॉर्डर पर टैंक कर बिछाए हुए थे, वह तैयारी फेल हो गई थी।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, सन् 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और अरुणाचल ने डटकर उसका सामना किया और चीन को खदेड़ना का काम किया। तब के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि गुड बाय अरुणाचल प्रदेश। उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता ने तय किया है कि अगली सरकार नरेंद्र मोदी की होगी। श्री शाह ने यहां वादा किया कि सरकार बनने के बाद वह अरुणाचल प्रदेश में नया एम्स बनाएंगे।

नागपुर (महाराष्ट्र)

'भाजपा सरकार आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देती है'

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 9 अप्रैल को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आतंकवादियों के साथ सिर्फ 'इलू-इलू' कर सकते हैं, जबकि बीजेपी सरकार उनको मुंहतोड़ जवाब देती है। श्री शाह ने यह बात महाराष्ट्र के नागपुर में एक रैली को संबोधित करने के दौरान कही। श्री शाह ने इसके साथ यह भी कहा कि राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि भाजपा सत्ता में है और वह आंतकवादियों को उसी के भाषा में जवाब देने में विश्वास रखती है।

श्री शाह ने कहा, "पाकिस्तान के बालाकोट स्थित आतंकवादियों के कैंप पर एयर स्ट्राइक के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी शोक मना रही थी, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर आप आतंकवादियों के साथ इलू-इलू करने चाहते हैं तो आपको यह याद रखना चाहिए कि बीजेपी इस समय केंद्र की सत्ता में है। भाजपा

आतंकवादियों को उसी के भाषा में जवाब देने में विश्वास रखती है।"

श्री अमित शाह ने इसके साथ ही राहुल गांधी पर हिंदुओं को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। श्री शाह ने कहा, 'राहुल गांधी ने पूरे दुनिया में हिंदू समुदाय को बदनाम करने का काम किया है। उन्हें इसके लिए चुनाव से पहले हिंदुओं से माफी मानना चाहिए।'

कांग्रेस अध्यक्ष पर चुटकी लेते श्री शाह ने कहा, "यह राहुल बाबा अपने गठबंधन के लिए केरल के अंदर ऐसी सीट पर जाकर खड़े जुलूस निकालते है, तो भारत है या पाकिस्तान का जुलूस है। मालूम ही नहीं पड़ता, ऐसी जगह जाकर खड़े हैं।"

जम्मू-कश्मीर पर श्री शाह ने कहा, 'उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। मैं राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला को बताना चाहता हूं कि कश्मीर भारत से कभी अलग नहीं हो सकता, चाहे बीजेपी सत्ता में रहे या ना रहे।'

कासगंज (उत्तर प्रदेश)

'एक-एक घुसपैठिए को देश से बाहर कर देंगे'

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पटियाली में 11 अप्रैल को सपा, बसपा एवं कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा मौनी बाबा का शासन था, तो दुश्मन सिर काट कर ले जाते थे। मोदी सरकार ने पुलवामा हमले के 13वें दिन पाक में जाकर जवाब दिया। यह गठबंधन चुनाव के बाद तार-तार हो जाएगा। अबकी सरकार बनी तो देश से घुसपैठियों को खदेड़ देंगे।

श्री अमित शाह ने पार्टी प्रत्याशी सांसद श्री राजवीर सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित करने से पहले माइक पर भारत माता के जयकारे लगवाए। इसके बाद तुलसीदास, भगवान वराह व एटा-कासगंज के बारे में कहा कि बंदी के कगार पर पहुंचे घुंघरू-घंटी उद्योग को सरकार ने संजीवनी दी है। एटा के मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि गिनाईं। उन्होंने कहा कि चुनाव में दो खेमे हैं- एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ विपक्ष। बुआ-भतीजे का गठबंधन कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर रहा है। वर्षों तक एक-दूसरे का चेहरा न देखने वाले अब साथ हैं। चुनाव के बाद यह गठबंधन तार-तार होने वाला है। जातिवादी पार्टी देश का भला नहीं कर सकतीं। भाजपा ने शौचालय दिए। घर दिए। गैस चूल्हा दिए, मगर जाति नहीं पूछी। सत्ता मांगने वाली सपा-बसपा अपने 15 वर्ष के शासन की तुलना भाजपा सरकार से कर लें। इनकी सरकारों में पलने वाले गुंडे एनकाउंटर के डर से आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हमने 'निजाम' यानी नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इमरान मसूद, आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से मुक्ति दिलाई है। पांच वर्ष और मोदी जी को मिल जाएं तो भारत महाशक्ति बन जाएगा। इसके लिए जात-पात को भूलकर वोट करना होगा।

उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देंगे। 60 वर्ष की उम्र होने पर किसानों को पेंशन देंगे। एयर स्ट्राइक पर उन्होंने कहा कि देश भर में जश्न मना, लेकिन दो जगह मातम था, पाक व उसके साथी विपक्षी खेमे में। घुसपैठिए चिन्हित करने पर अजीत सिंह रोते हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। वोट की अपील करते हुए कहा कि घर जाकर 50-50 लोगों को फोन करें। श्री शाह ने वंदे मातरम के साथ अपनी बात को खत्म किया।

सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल)

'सत्ता में लौटने पर देशभर में लागू करेंगे एनआरसी'

भाजपा केंद्र की सत्ता लौटने पर जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा देगी और देशभर में नागरिकों के लिए एनआरसी लागू करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने दार्जिलिंग से पार्टी प्रत्याशी राजू विष्ट के समर्थन में 11 अप्रैल को कलिम्पोंग में आयोजित चुनावी सभा में यह दावा किया। उन्होंने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा- 'ममता और विपक्षी नेता एयर स्ट्राइक से नाखुश हैं।

वे सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एयर स्ट्राइक से दो जगह मातम था- एक पाकिस्तान और दूसरा ममता बनर्जी के कार्यालय में।' श्री शाह ने ममता से कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री की मांग पर अपना रूख स्पष्ट करने को कहा। श्री शाह ने कहा- 'हम ममता की तरह घुसपैठियों का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। हम सुनिश्चित करेंगे कि देश के हरेक हिंदू एवं बौद्ध शरणार्थी को नागरिकता मिले।'

मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी द्वारा प्रस्तावित महागठबंधन पर निशाना साधते हुए श्री शाह ने कहा-'मुझे हैरत होती है कि कांग्रेस और माकपा क्यों तृणमूल की आलोचना कर रही हैं जबकि वह उनके सहयोगी हैं।' वहीं रायगंज की चुनावी सभा में बांग्लादेशी घुसपैठियों को 'दीमक' बताते हुए श्री शाह ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेगी।

भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस तुष्टिकरण, माफियागीरी और चिटफंड घोटालों में लगी है। घुसपैठिये दीमक की तरह हैं। वे अनाज खा रहे हैं, जो गरीबों को जाना चाहिए। वे हमारी नौकरियां छीन रहे हैं। 'टीएमसी' (तृणमूल कांग्रेस) के 'टी' का मतलब 'तुष्टीकरण', 'एम' का मतलब 'माफिया' और 'सी' का मतलब चिटफंड है। सत्ता में आने के बाद भाजपा इन दीमकों का पता लगाकर उन्हें देश से बाहर निकालेगी। श्री शाह ने आगे कहा- 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही गोरखाओं के साथ हैं। ममता बनर्जी ने पहाड़ की शांति को भंग करने के साथ ही उसे तबाह कर दिया है। बंगाल की जनता अब परिवर्तन के लिए तैयार है। ■

प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम सन्देश

भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से लाइव सैटेलाइट को मार गिराया: नरेंद्र मोदी

भारत ने अंतरिक्ष में एंटी मिसाइल से एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराते हुए 27 मार्च को अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति के तौर पर दर्ज करा दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा,''मिशन शक्ति के तहत स्वदेशी एंटी सैटेलाइट मिसाइल 'ए-सैट' से तीन मिनट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया गया।" यहां प्रस्तुत है उनके संदेश का पूरा पाठः

मेरे प्यारे देशवासियों,

आज, 27 मार्च, कुछ ही समय पूर्व, भारत ने एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति- स्पेस पावर - के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के तीन देश- अमेरिका, रूस और चीन - को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है, जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। हर हिन्दुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है।

कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में तीन सौ किलोमीटर दूर एलइओ (लो अर्थ ऑर्बिट) में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। एलइओ (लो अर्थ ऑर्बिट) में यह लाइव सैटेलाइट, जो एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट (ए-सैट) मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है। सिर्फ तीन मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है।

मिशन शक्ति- यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था, जिसमें बहुत ही उच्चकोटि की तकनीकी क्षमता की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं। हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है कि यह पराक्रम भारत में ही विकसित एंटी सैटेलाइट (ए-सैट) मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है।

सर्वप्रथम मैं मिशन शक्ति से जुड़े सभी डीआरडीओ वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा अन्य संबंधित कर्मियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस असाधारण सफलता को प्राप्त करने में योगदान दिया। आज फिर इन्होंने देश का मान बढ़ाया है, हमें हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है।

अंतरिक्ष आज हमारे जीवन-शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हमारे पास पर्याप्त संख्या में उपग्रह उपलब्ध हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहें हैं, जैसे- कृषि, रक्षा, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, संचार, मौसम, नेवीगेशन, शिक्षा आदि।

हमारे उपग्रहों का लाभ सभी को मिल रहा है, चाहे वो किसान हों, मछुआरें हों, विद्यार्थी हों, सुरक्षा-बल हों। दूसरी ओर चाहे वो रेलवे हो, हवाई जहाज, पानी के जहाजों का परिचालन हो, इन सभी जगह उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है।

विश्व में स्पेस और सैटेलाइट का महत्व बढ़ते ही जाने वाला है। शायद जीवन इसके बिना अधूरा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इन सभी उपकरणों की सुरक्षा पुख्ता करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज की एंटी सैटेलाइट (ए-सैट) मिसाइल भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और भारत की विकास यात्रा की दृष्टि से देश को एक नई मजबूती देगा। मैं आज विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने जो नई क्षमता प्राप्त की है यह किसी के विरुद्ध नहीं है। यह तेज गति से आगे बढ़ रहे हिन्दुस्तान की रक्षात्मक पहल है।

भारत हमेशा से ही अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के विरुद्ध रहा है और इससे इस नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। आज का यह परीक्षण किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा संधि-समझौतों का उल्लंघन नहीं करता है। हम आधुनिक तकनीक का उपयोग देश के 130 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके कल्याण के लिए करना चाहते हैं।

इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए एक मजबूत भारत का होना आवश्यक है। हमारा सामरिक उद्देश्य शांति बनाये रखना है, न कि युद्ध का माहौल बनाना।

प्यारे देशवासियों,

भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में जो काम किया है, उसका मूल उद्देश्य भारत की सुरक्षा, भारत का आर्थिक विकास और भारत की तकनीकी प्रगति है। आज का यह मिशन इन सपनों को सुरक्षित करने की ओर एक अहम कदम है, जो इन तीनों स्तंभों की सुरक्षा के लिए आवश्यक था।

आज की सफलता को आने वाले समय में एक सुरक्षित राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र और शांतिप्रिय राष्ट्र की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम आगे बढ़ें और अपने आप को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करें।

हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने तथा अपने लोगों के जीवन-स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाना ही होगा। सभी भारतवासी भविष्य की चुनौतियों का सामना आत्म-विश्वास से करें और सुरक्षित महसूस करें, यही हमारा लक्ष्य है।

मुझे अपने लोगों की कर्मठता, प्रतिबद्धता, समर्पण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। हम निस्संदेह एकजुट होकर एक शक्तिशाली, खुशहाल और सुरक्षित भारत का निर्माण करें। मैं ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूं जो अपने समय से दो कदम आगे की सोच सके और चलने की हिम्मत भी जुटा सके। सभी देशवासियों को आज की इस महान उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में लोक सभा 2019 के लिए भाजपा संकल्प पत्र जारी करने के अवसर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री सर्व श्री राजनाथ, श्री अरुण जेटली, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री थावरचंद गहलोत और भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल

चित्रदुर्ग (कर्नाटक) की एक रैली में जनाभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

जूनागढ़ (गुजरात) की एक रैली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते गुजरात भाजपा नेतागण

कोरापुट (ओडिशा) में कार्यकर्ताओं व समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) की एक चुनावी जन सभा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-19